[Shri Niren Ghose]

From reliable sources, it is learnt that there is a conspiracy afoot to take the Museum away from Calcutta. Naturally, such a step is bound to cause much public concern. On the top of this, the institution has been suddenly closed in the third week of December, without assigning any reason therefor. Even on the last day when the Museum was open, there were 800 visitors. This closure has created public concern. Besides, 250 employees have been thrown out of employment. There is a growing public demand that the Museum be opened forthwith. It is reported that Services of one employee has been terminated and 6 others put under suspension without putting forward any reason. Whatsoever. I, Therefore, demand that Victimisation, if any, of employees be revoked and any plan to take the Museum away from Calcutta be abandoned.

(ii) REPORTED POWER CRIZIS IN BLHAR.

श्री चन्द्रदेव प्रसाद वर्मा (आरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय का उल्लेख करना चाहता हूं :–

बिहार अभी भीषण विद्युत् संकट से गुजर रहा है, जिसकी जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार के ऊपर भी आती है । रेल मंत्रालय तथा ऊर्जा मंत्रालय की आपसी खींचातानी के कारण कोयले की उपलब्धि में कमी एंव अनियमितता रहती है । फलतः विद्युत् उत्पादन में बाधा हो रही है । साथ ही बिहार विद्युत् बोर्ड एंव भेल एक दूसरे पर विफलताओं का दोषारोपण करते आ रहे है । इस आपसी दोषारोपण के कारण बिहार की जनता त्रस्त है । कृषि चौपट होती जा रही है । किसानों में भंयकर असंतोष है । उद्योगों, खासकर लघु उद्योगों की हालत बदत्तर होती जा रही है । यहां तक कि अस्पतालों में रोगियों का इलाज तथा आपरेशन भी नहीं हो पाता है । अतः शीघ्र ही बिहार में विद्युत् संकट दूर करने हेतु रेल और उर्जा मंत्रालय आपसी खींचातानी को समाप्त करे ।

12.47 hrs.

ANNOUNCEMENT *RE*s TIME OF ADJOURNMENT OF THE HOUSE ON 29-1-1980.

MR. SPEAKER: Members are aware that tomorrow, Beating Retreat function will be held. In order to enable Members to witness the Beating Retreat, I propose to adjourn the House at 4 p.m. tomorrow. I have discussed it with the leaders of parties and groups, and they have all agreed to it.

12.48 hrs.

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—*Contd.*

MR. SPEAKER: Now we proceed with the discussion on the Motion of Thanks. Now Mr. Charan Singh. But before Chaudhri Saheb takes the floor, I would like to point out that we have allotted time according to the number of Party members. Chaudhri Saheb has taken some time, and 8 minutes more are left. We have agreed, all of us, that we shall not have the sitting of the House after 2nd February. So, we have to work on that limited time. Please make your speeches accordingly, so that every Member of the party, whom soever you want to speak, may be able to do so.

SHRI JYOTIRMOY BOSU (Diamond Harbour): A submisison Sir, It has been the convention of the House that whenever leaders of the parties speak, they are given a little more time than what is strictly due to them.

MR. SPEAKER: Whatever is available, will be given. Mr. Bosu, I cannot give time, which is not in my hands. I have taken the consensus of the leaders and then I have decided. Now Chaudhri Saheb.

श्री चरण सिंह (बागपत) : अध्यक्ष महोदय, मेरा अपना ख्याल यह था कि मुझको काफी समय मिलेगा ऐड्रेस में जो सवाल उठाये गए हैं उनका जवाब देने के लिए, लेकिन अब आपने तय किया है कि दूसरे लोगों के मशविरे से, मैं शायद उसमें शामिल नहीं था, आमतौर पर लीडर आफ दि अपोजीशन और लीडर आफ दि हाउस के लिए ऐसी डिबेट में कोई समय मुकर्रर नहीं होता, लेकिन अगर मुझे 8 ही मिनट बोलना है तो फिर एक-एक प्वाइंट दो-दो सैकंड में बतला देता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा प्रेसाइज कर दीजिए ।

श्री चरण सिंह : कल मैंने यह कहा था श्री एस० एम० कृष्णा के जवाब में--उन्होंने यह फर्माया कि हिन्दुस्तान आर्थिक और सैनिक दृष्टि से मजबूत हुआ, मैंने कहा नहीं । आर्थिक दृष्टि से मैंने यह कहा कि पिछले तीस साल जो कांग्रेस पार्टी के थे उसमें उन्होंने 25 अरब रुपये का 18.8 मिलियन टन गल्ला बाहर से मंगाया । प्रधान मंत्री बैठी थी, उस वक्त उन्होंने कहा कि यह बात गलत है । मैं अब आपको यह बतलाना चाहता हूं कि फूड स्टेटिस्टिक्स की जो बुलेटिन 1978 में निकली है उसकी फिगर्स ये हैं कि 1974 में 4874 हजार टन अनाज आया जिसकी कीमत थी 463 करोड़, सन् 75 में 7407 हजार टन आया जिसकी कीमत थी 10 सौ करोड़ 57 लाख 90 हजार और 1976 में 6515 हजार टन गल्ला आया अमेरिका से जिसको कीमत थी 982 करोड़ । तीनों को मिला कर हुआ 1 करोड़ 87 लाख 96 हजार टन जिसका मतलब है 18.8 मिलियन टन और 19--20 मिलियन टन वह छोड़ कर गई थीं । कीमत थी उसकी 25 अरब 3 करोड़ रुपये । लिहाज़ा जो मैंने फैक्ट्स रखे थे जिनको प्राइम मिनिस्टर ने डिस्प्यूट किया था वह उनके ही अपने आफिशियल रेकार्ड से साबित है । इसलिए यह कहना कि कांग्रेस के जमाने में आर्थिक दृष्टि से और मिलिट्री की दृष्टि से देश मजबूत हुआ, गलत है । ... (**व्यवधान**)*

MR. SPEAKER: This is not the way. Nothing should be recorded without my permission.

श्री चरण सिंह : ऐड्रेस में यह कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी जनता के हर सेक्शन को, देश के हर प्रदेश को, हर कोने को और हर प्रकार की राय को रेप्रेजेन्ट करती है । यह उनका क्लेम गलत है, अनफाउन्डेड है । इसके लिए कोई आधार नहीं है । आपने यह भी कहा है कि हम कम्यूनल डिफरेंसेज, सेक्शनल डिफरेंसेज और इस तरह के इन्फलुएंसेज पर निर्भर नहीं करते हैं, हम पीपल ऐज एक होल को रेप्रेजेन्ट करते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि जब डी० एम० के० से फैसला हुआ तो वह रीजनल पार्टी नहीं थी क्या? वह रीजनल पार्टी थी । सैयद अब्दुल्ला बुखारी साहब से फैसला किया, उनकी कुछ कम्यूनल डिमांड्स को माना, तो वह कम्यूनल डिफरेंसेज का फायदा उठाने की कोशिश की या नहीं की ? दोनों चीजों से इन्कार नहीं किया जा सकता ।

रहा यह कि आप जनता एज ए होल को रेप्रेजेन्ट करते हैं तो बिहार और यू० पी० में 35 से 37 फीसदी आपके वोट आए हैं और वैसे सारे देश में साढ़े बयालीस फीसदी वोट आए हैं, तो यह क्लेम भी आप का आधाररहित है । इसके अलावा केरल और वेस्ट बंगाल का जहां तक ताल्लुक है उसकी नुमाइन्दगी कांग्रेस पार्टी बिल्कुल नहीं करती है । लिहाज़ा यह क्लेम भी बोस्टफुल है, आधार रहित है कि आप देश को रेप्रेजेन्ट करते हैं इर्रेस्पेक्टिव आफ सेक्शनल डिफरेंसेज एटसेट्रा ।

उन्होंने यह भी कहा है कि वह अब स्टेबल गवर्नमेंट देंगे, यह भी क्लेम अनफाउन्डेड है । आप की बड़ी भारी मेजारिटी थी सन् 75 में, फिर भी आप मुल्क को नहीं चला पाए और आपको एमर्जेंसी लागू करनी पड़ी । इसके अलावा सन् 1966 से 77 तक 11 साल के अंदर अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट की लीडरशिप ने, कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप ने 27 बार निकाला, कभी इस स्टेट मिनिस्ट्री को, कभी उस स्टेट मिनिस्ट्री को । लिहाज़ा स्टेबल गवर्नमेंट देने का दावा और वादा, यह भी आधाररहित है ।

आपने यह भी फरमाया कि जब तक आप आफिस के बाहर रहे इस बीच में कम्यूनल और डिविजिव फोर्सेज, यानी साम्प्रदायिक और देश में फूट डालने वाली ताकतों को बढ़ाया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह वाकया है या नहीं कि हर पांच साल बाद जब इलेक्शन आया उसके ठीक छः महीने पहले हरिजन कांफ्रेंसेज, माइनारिटी कांफ्रेन्सेज और बैकवर्ड क्लासेज कान्फ्रेन्सेज की गई या नहीं ? हर पांच साल बाद जब इलेक्शन आया तब जो ये कान्फ्रेन्सेज की गईं, ये किसलिए की गई ? ... (**व्यवधान**)* ....

MR. SPEAKER: Nothing should be recorded without my permission.

श्री चरण सिंह : जो वाकयात हैं उन पर शोर मचाने से कोई काम नहीं चलेगा । आप जरा शान्ति से सुनिए । (**व्यवधान**)

जहां तक शान्ति और व्यवस्था में डेटेरियोरेशन, गिरावट की बात है, ठीक है लेकिन जबसे आपने चार्ज लिया तब से दिल्ली में क्या हो रहा है ? ? (**व्यवधान**) लोकदल के जमाने में या जनता पार्टी के जमाने में अगर एक मर्डर होता था तो चारों तरफ शोर मचता, कि ला एण्ड आर्डर खत्म हो गया, लेकिन अब कोई शोर मचाने वाला नहीं है ।

*Not recorded.

[श्री चरण सिंह]

इसके अलावा जो लोग वायलेंस पैदा करते हैं उनको इस तरह का कोई अधिकार दूसरों को टांट करने का नहीं है। अभी 4-5 दिन पहले कांग्रेस पार्टी के तीन एम० पीज० ने हजारों आदमियों के जुलूस के साथ एक तरह से वायलेंट डिमांस्ट्रेशन लखनऊ में किया। (**व्यवधान**)** क्या यह वाकया है या नहीं? 23 तारीख को जुलूस निकाला गया। (**व्यवधान**)** तीन एम० पीज० थे जिन के नाम बता देता हूं—बहराइच के एम० पी०, अलमोड़ा के एम०पी० और. . .(**व्यवधान**)**

अध्यक्ष महोदय : मि० टाइटलर, आप आराम से बैठिये।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में कोई ला ऐंड आर्डर नहीं है, यह मेरे पास अखबार है। (**व्यवधान**)**

श्री चरण सिंह : मैं अपने दोस्तों से अर्ज करना चाहता हूं कि जब आपका मौका आये तब जरूर कहिएगा। अगर आप मुझको बोलने नहीं देंगे तो इधर की तादाद कम सही, आपको भी फिर बोलने का मौका नहीं मिलेगा। (**व्यवधान**)**

MR. SPEAKER: Order, order. Nothing is to be recorded without my permission. Please take your seats. Mr. Tytler, this is not the way. Please behave like hon. Members of this House.

श्री आरिफ मोहम्मद खां (कानपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोई व्यवधान नहीं डालता लेकिन एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। (**व्यवधान**)

MR. SPEAKER: Under what rule?

श्री आरिफ मोहम्मद खां : वह मैं बाद में बताऊंगा। (**व्यवधान**)

MR. SPEAKER: Under what rule you want to raise a point of order? I want the rule. You are unnecessarily taking up the time of the House.

It is lunch hour.

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष जी, मैं एक बात कहना चाहता हूं। ऐसी चीज हो सकती है कि मैं कोई बात गलत कह रहा हूं या आप उसको गलत समझ रहे हों। आप को मौका मिलेगा—बोलने का और आप उस वक्त उस का जवाब दे सकते हैं। लेकिन बीच में रोकेंगे तो यह सभा नहीं चलेगी—सीधी सी बात है।

मैं यह अर्ज कर रहा था कि यह जलूस निकला था, कांग्रेस पार्टी के लोगों ने निकाला था, तीन एम० पी० उस में शामिल थे और जो कौन्सिल हाउस में जबरदस्ती घुसना चाहते थे।

MR. SPEAKER: You may continue at 2 P.M. after lunch break.

13.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at three minutes past Fourteen of the Clock.

(Mr. Speaker *in the Chair*)

MEMBER SWORN

Shri Atal Bihari Vajpayee (New Delhi)

MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—contd.

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय मैं जानता हूं कि समय कम है और मुझे बहुत बातें कहनी थीं लेकिन अब मैं केवल एक दो बातें कह कर ही अपना भाषण समाप्त कर दूंगा।

प्रेसीडेंट एड्रेस में यह कहा गया है कि नियोजन के जरिए या प्लानिंग के जरिए सामाजिक और आर्थिक तब्दीलियां लाने की कोशिश की जाएगी। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि अगर पुरानी नीतियों का अनुसरण किया जाएगा, तो फिर किसी प्रकार की कोई चेन्ज या तब्दीली नहीं आएगी और जो सोशल चेन्ज की बात है, सामाजिक परिवर्तन की बात है, तो उसके दो मोटे से रूप हैं। एक तो यह है कि हमारे यहां बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और दूसरी सोशल प्राब्लम है जो हमारा सोशल सिस्टम है, वह कास्ट्स पर बेस्ड है, जन्मगत जिस का आधार है और वह हमारे यहां एक दूसरी बड़ी समस्या है।

जहां तक बेरोजगारों का सम्बन्ध है, हर प्लान में गवर्नमेंट के आंकड़ों के अनुसार या प्लानिंग कमीशन के आंकड़ों के अनुसार, बेरोजगारों की तादाद बराबर बढ़ती चली गई है। पहली प्लान के बाद प्लानिंग कमीशन का यह अन्दाजा था कि 3·3 मिलियनस यानि 33 लाख बेरोजगार हैं और चौथी प्लान के बाद वे आंकड़े बढ़ कर 13.6 मिलियन हो गये।

**Not recorded.

इसका मतलब यह हुआ कि 1 करोड़ 36 लाख आदमी बेरोजगार हैं। जो एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज हैं, कामदिलाऊ दफ्तर हैं उन में जिन नौजवानों ने अपने नाम रजिस्टर करवाएं हैं उनकी संख्या 1971 में 42 लाख 21 हजार थी। सन् 1977 में उनकी तादाद 1 करोड़ दो लाख 39 हजार हो गई। यानी उनकी तादाद बढ़ गई। यह तो बेरोजगारी का हाल है।

अब कास्ट सिस्टम और जातिगत आधार पर जो बुराइयां हमारे देश में हैं उनके बारे में मैं नहीं कह सकता कि रूलिंग पार्टी कहां तक जाने को तैयार है। मेरी प्रधान मंत्री जी से इस बारे में बात हुई थी और मैंने उन्हें कहा था कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कास्ट सिस्टम। उसी की वजह से हमारे समाज में बहुत सी खराबियां पैदा हुईं और सैकड़ों वर्षों तक हमारा मुल्क गुलाम रहा। यह सब केवल जात-पांत के कारण हुआ।

एक जाति की डेफिनिशन क्या है? यही है कि एक समूह जो कि आपस में मेरिज, विवाह करता है वह एक कास्ट कहलाती है। हम उन लोगों को किसी दूसरी कास्ट में विवाह करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। हम किसी आदमी को बी० ए० पास करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकते कि उसका सोना इतना हो, उसकी ऊंचाई इतनी हो, उसके हार्ट में कोई रोग न हो। लेकिन जब हम गजेटेड सर्विसिज में लड़के को लेते हैं तो उसके लिए हम क्वालिफिकेशन रखते हैं कि वह ग्रेजुएट हो, या इंजीनियरी की डिग्री उसके पास हो, हेल्थ का सर्टिफिकेट उसके पास हो। अब हमने उसकी फिजिकल पावर और ब्रेन पावर का तो इम्तिहान ले लिया लेकिन उसका हार्ट भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसका हेड। जब कोई लड़का किसी सर्विस में आयेगा या लेजिस्लेचर में आयेगा तो वहां उसका हार्ट भी काम करेगा। एक दृष्टि से उसके हार्ट में ही सिम्पैथी, एण्टीपैथी लव और हेट पैदा होते हैं। इसी से जिसको हम नेरो सिम्पैथी या तंगदिली कहते हैं, पैदा होते हैं। यह हमारे समाज में और हमारी परिस्थितियों में है। यह जो परिस्थिति है वह जन्मगत जात-पांत के कारण है।

हमारी जो क्लास टू और क्लास वन की गजेटेड सर्विसिज हैं वे मुश्किल से तीन या चार परसेंट होंगी। उनके लिए हम उसके हेड और ब्रेन का इम्तिहान तो लेते हैं लेकिन उसके हार्ट का नहीं। अगर उसका हार्ट इतना बुरा हो कि वह हिन्दुस्तान के सारे आदमियों के लिए एक जैसी हमदर्दी न रखता हो तो हमारा काम चलने वाला नहीं है। इसलिए मेरा कहना यह है कि हम एक ऐसी कंडीशन लगायें कि जो भी इस सर्विस में आये वह इण्टरकास्ट मैरिज के लिए तैयार हो।

माननीय प्रधान मंत्री जी उस समय तैयार नहीं हुई थी, मुमकिन है अब तैयार हो जाएं। (व्यवधान) मैं यह कह रहा हूं कि वे उस समय तैयार नहीं थीं। यह वाकया है। अब अगर वे तैयार हो जाए तो मैं इसे देश की खुशकिस्मती समझूंगा। यह तो हुआ सोशल सिस्टम का हाल।

अब मैं इकोनोमिक सिस्टम पर आता हूं। इसका क्या हाल है? हमारी माननीय प्रधान मंत्री जी पहली बार प्रधान मंत्री 1966 में बनी थीं। उस समय अर्थात् 1964-65 में अगर एक मिलियन या दस लाख की आबादी वाले मुल्क को एक मुल्क माना जाए तो उन 125 मुल्कों में गरीबी की दृष्टि से हमारा स्थान 85वां था। अर्थात् 84 देश हमसे मालदार थे और 40 देश हमसे गरीब थे। उसके आठ साल बाद अर्थात् इंदिराजी के चार्ज लेने के सात साल के बाद जहां हमारा स्थान ऊपर चढ़ना चाहिए था, यानी हमारा स्थान 70 पर या 65 पर होना चाहिए था वहां हमारा स्थान 103वां हो गया। हम से जो गरीब देश थे उनमें से 18 देश हम से मालदार हो गये, हम से ऊपर चढ़ गये। यह 1973 की बात है। उसके तीन साल बाद, जब कि माननीय इंदिराजी का शासन काल था, हमारे देश का स्थान 111वां हो गया। 110 देश हमसे मालदार हो गये। यह तो गरीबी का हाल है।

1967-68 में जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोग थे उनका प्रतिशत 1978 में और भी बढ़ गया। प्लानिंग कमीशन के नोट्स आप देख लें। उनके मुताबिक आज 47 परसेंट आदमी गरीबी की रेखा के नीचे रहते है, 41 प्रतिशत शहरों में और 47–48 प्रतिशत गांवों में। पावर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों की तादाद समय गुजरने के साथ साथ बढ़ती गई है बजाय घटने के। कंसेंट्रेशन आफ इकॉनोमिक पावर, आर्थिक सत्ता का केन्द्रीय करण बजाय घटने के बढ़ता ही गया है। बिड़ला, टाटा के आंकड़े आप देख लें। मेरे पास समय नहीं है कि मैं उन आंकड़ों को आप के सामने रख सकूं। आंकड़े इस वक्त मेरे पास मौजूद हैं। 1951 में जितनी उनके पास दौलत थी आज उससे कहीं ज्यादा वह बढ़ गई है, बजाय कम होने के।

एग्रीकलचरल वर्कर और नान एग्रिकलचरल वर्कर में पहले 100 और 178 का अनुपात था 1951 में और आज वह 100 और 366 हो गया है। आपके तीस साल के राज्य का यह नतीजा है कि अमीर आदमी और अमीर होता गया है गांव और शहर का फर्क बजाय कम होने के बढ़ता गया है बेरोजगारों की तादाद बढ़ती गई है।

इन शब्दों के साथ मैं अपने कथन को समाप्त करता हूं।

SHRI JANARDHANA POOJARY (Mangalore): Mr. Speaker, Sir, I rise to support the motion of thanks moved by Shri S. M. Krishna, on the President's Address. We have seen the Janata rule for the last 28 months and also the rule of Lok Dal and Congress alliance for the last six months.

At the very outset, I submit that during this period, the problems like unemployment, deaths due to starvation, natural calamities like cyclone, drought, family planning, economic development had become secondary issues whereas strikes, gharoes and the trade union rivalry and student indiscipline, commissions of inquiries and scandals had become the order of the day. In fact during this period, it was not a Government of the people, by the people and for the people, but of the Janata party, for the Janata Party and by the Janata Party. The foreign tours had become contaguous. They had monopolised it in every field. It was often said "join the Janata cabinet and tour the world." What had happened to socialism? The Janata Party had taken the country from socialism to Capitalism, and mixed economy. Anti-public-sector views expressed by Janata Party Members like Dr. Swamy were not in tune with the planned growth of national economy. His proposal for de-nationalisation was aimed at enriching a few monpolists and also handing over the economy of this country to the vested interests.

The paramount importance of the public sector in bringing about social reformation cannot be under-estimated. In a country like ours, where there is the problem of growing population and where the people are struggling because of exploitation, social insecurities, unemployment, etc., the capitalist system cannot be an answer or a remedy and the glaring disparities that we see among our people is a curse on our society.

14.15 hrs.

[SHRI TRIDIB CHAUDHURY *in the Chair*]

Only socialism could bring fruits or benefits to the masses of this country. Unfortunately, that had been given up during the Janata rule.

Not only this. The people had even lost their faith in the ability of the leaders of the Janata Party to rise to the expectations of the people and to carry the country forward. Fortunately, Mrs. Indira Gandhi at the helm of affairs can change the situation. In the words of Mr. Charan Singh, even though I feel that these are not decent words, the Janata leaders turned out to be a bunch of impotents and, if I may submit, I can say that they have turned out to be old cats. The less said about them the better. Their memory leaves a bad taste in the mouth. An era of despondency, an era of frustration and an era of demoralisation is over. Now, by having Mrs. Indira Gandhi at the helm of affairs, the people of the country expect these problems to be solved as soon as possible. By bringing Mrs. Indira Gandhi at the helm of affairs, the people of this country have asserted their right in rejecting the elected representatives who misused the mandate given to them and have also re-asserted their faith in the democratic values of the country.

Further, it has been proved and established beyond doubt that the people of this country have once again shown that the people are supreme and not the leaders of the parties. They have brought back Mrs. Indira Gandhi with a clear mandate because they feel that they were cheated and betrayed by the Janata Party leaders who took them for a ride.

It is often said after the elections that the people of this country have once again proved their love for democracy need not necessarily mean an ineffective and inefficient

administration. It is a strong Government, could be fully democratic as well as effective and efficient. But during the Janata rule, much tom-tomed freedom was enjoyed only by a coterie of uraders, black-marketeers, smugglers and also the people with foreign links. That was the Janata style of freedom which was given to this country. What happened to the poor people who constitute the bulk of the population? In fact, they suffered a lot and they were not in a position to enjoy the fruits of this freedom.

The people of this country have now reposed their faith in Mrs. Indira Gandhi. Why? It is because Mrs. Indira Gandhi has promised them stability, rule of law, an effective and efficient Government. The other day, Mr. Charan Singh was saying that our party members have been eulovising Mrs. Indira Gandhi and praising her. Yes. After 1977 debacle, I have seen that you people were speaking on the floor of the House—you were not allowing us to speak—criticising and scolding Mrs. Indira Gandhi and Mr. Sanjay Gandhi throughout the day, from 11 A.M. to 6 P.M. without break. You were going against democratic values of the country. Now, these young people, the youngsters, who have come will rise to the occasion and will show the way to elders and correct you. (*Interruptions*). When you have been speaking, I have not interrupted you. When your leader was speaking, I did not interrupt him.

The people have given a clear verdict. The verdict is deliberate and positive. It is not a negative one. The last mid-term election was not an ordinary election. It was a referendum exercised by the people of this country to bring Mrs. Indira Gandhi back, fully knowing the consequences, because the people of this country were against casteims, the people of this country were against regionalism, the people of this country were against communalism, the people of this country were against political fragmentation, the people of this country were against opportunism, defections, social and economic chaos. Definitely, the people of this country have humbled and humiliated those leaders who are sitting today in the Opposition and also the people who were in the House and who are now thrown out of this House. These people have been humiliated by the people of this country. Why? It is because they played with the dignity and honour of the great people of this great country. The people of this great country today brought back Mrs. Gandhi with a big mandate because they wanted to demolish the caste barriers created especially by Shri Charan Singh. Not only that, but they wanted her to eradicate regionalism, they wanted her to eradicate communalism, they wanted her to foster a sense of political commitment, they wanted her to reduce economic disparities, they wanted to reduce concentration of wealth, they wanted her to bring down prices and they wanted Mrs. Gandhi to launch employment oriented schemes and to provide the people with the bare necessities of life.

What had these people done? The Janata Government had pushed the country to the brink of an economic pricipice. The perennial shortage of coal, the perennial shortage of power, the perennial shortage of kerosene and diesel have shaken the economy of the country. Normalcy has to be restored on this front. What has happened is that the rise in prices and the non-availability of kerosene and diesel have in particular contributed to the debacle of the Janata Government and the Lok Dal rulers. Not only that, in the northern parts of the country millions of people are plunged in darkness after sun set and are without tractors and diesel engines which are vital to the rural economy lie idle. These things which are meant for rural economy are lying idle today and the people of this country look up to Mrs. Gandhi

[Shri Janardhana Poojary]

to solve the problems as early as possible. Apart from this, law and order, which we had been talking about during the Elections has to be restored, and the people have to be given a sense of security.

Now, I refer to an Hon. Member of this House, Shri Jagjivan Ram. This Election has proved once again that no one can claim today that he is the leader of a particular community. The Harijans of this country—that is, the weaker sections of this country—have reposed their faith in the leadership of Mrs. Gandhi and have preferred Mrs. Gandhi to Mr. Jagjivan Ram, even though Mr. Jagjivan Ram had assumed that, with the help of the Harijans, he will come to power. He had claimed that the Harijans were loyal to him.

I am now referring to Mr. Charan Singh, another leader in this Hon. House. What has he done? He wanted to divide the country. In what manner? He wanted to divide the country into narrow and vicious compartments and the people have discarded him. But one thing I may submit. Today, the Harijans, the weaker sections and the minority communities of this country have reposed their faith in the leadership of Mrs. Gandhi. It is but natural and legitimate. The weaker sections definitely expect social and economic benefits to accrue to those to whom these things have been denied. I submit, Sir, that this country was like a rudderless ship for the last 23 months. There was no sense of direction and no sense of commitment displayed because there was none. Unfortunately, this country, which was capable of moving mountains, was reduced to a lump. Who were responsible for this? Their leader and former Prime Minister Mr. Morarji Desai, their leader Mr. Jagjivan Ram, their leader and former Prime Minister Mr. Charan Singh was responsible.

Now, today these people have been talking about democracy. I will come to that—what is democracy and what these people mean. But I can submit only one thing. Now this country has to be re-infused with faith, desire, ambition, adventurism and dynamism of which it had been proud. It is not an exaggeration if I say that this could be done only by Shrimati Indira Gandhi. These are not the words of sycophants. This is the expectation of the people of this country. The people have learnt to assert their sovereignty, not only sovereignty but also supremacy. I can tell them what had happened during their period. They are now talking of democracy and democratic values. I have just now heard Mr. Charan Singh; he is apprehending dissolution of the Assemblies of Janata-ruled States as well as Lok Dal-ruled States. I want to point out what this gentleman, who is today speaking about democratic values and democracy, had done during his rule. As the Home Minister of this country, he had written threatening letters, letters threatening to dissolve the Congress-ruled States during the Janata rule. Not only that, they had also expelled from the House the elected representative from Chikmagalur, namely, Shrimati Indira Gandhi. They are today speaking about democratic values. What did they do during that period. They expelled as elected representative, Shrimati Indira Gandhi, without giving any cogent reason...

AN HON. MEMBER: Who says?

SHRI JANARDHANA POOJARY: I was present physically in the House then. Today the people have given a reply to that. Why have the people given this reply? Because you were responsible for insecurity, you were responsible for the instability, you were responsible for the chaos, you were responsible for the anarchy, in this country. That is why, the people of this country have given a correct answer. I had submitted this to you in my maiden speech immediately

after the 1977 elections; I had said this to the Janata rulers even though we were not allowed to speak because of constant interruptions; now our Leader is here and she is allowing the youngsters to speak, but in those days the Janata Members were not allowing us to open our mouth. I had said on the floor of the House after the 1977 elections that the people of this country would realise their mistake one day and that the day was not far off when people would once again bring back Shrimati Indira Gandhi after realising their mistake because the Janata Party was not in a position to give food, medicine and employment to the poor people of this country. And today the people have realised their mistake and have brought back Shrimati Indira Gandhi within a short span of time, that is, within 33 months. This should be kept in mind. I am not going to speak much. But let us realise one thing. We are aware of our responsibility. We are not for vendetta, we are not for vindictiveness. That is why, the day before yesterday, I have moved one amendment to the Motion. I have seen those people withdrawing criminal cases against Mr. George Fernandes. The former Prime Minister, Shri Charan Singh, today speaks about democratic values. What did he do when he was the Home Minister of this country? He had taken the step of withdrawing the cases against Mr. George Fernandes giving the reason that, under the changed circumstances, they were withdrawing the cases against Mr. George Fernandes. And what were the charges levelled against Mr. George Fernandes? They were offences punishable with death, with imprisonment for life. Such criminal cases against him were withdrawn. Today we are requesting our Government to withdraw the cases filed against Shrimati Indira Gandhi, Shri Sanjay Gandhi, Shri R. K. Dhawan and others. Why? The Special Courts Act was enacted only to wreck vengeance, to finish politically Mrs. Indira Gandhi and her family. Today I am requesting all the Members to cooperate with me in this. We are not for vindictiveness. We know that vindictiveness does not pay. Victimisation boomerangs. We know our responsibility. We are requesting the hon. Members from the Opposition side to co-operate in withdrawing the cases against these political opponents. Otherwise the people will definitely show their strength and in fact they have given the mandate to withdraw the cases against Mrs. Gandhi because they did not like political vendetta, they did not like political vengeance.

In conclusion I request the hon. Members of the House to support socialism because it will add upto the word Gandhism and Nehruism and in short, it will add upto the word humanism and lastly it will add upto the word Indiraism.

MR. CHAIRMAN: Mr. Chandraker.

Before you start, I may say that the time is very limited. For every group the time has been calculated. Of course, the ruling Congress Party has a larger number of speakers. Even then I would request individual members who are not leaders of groups to limit their speeches to ten minutes.

SHRI CHANDRAJEET YADAV (Azamgarh): Now that you have raised the question of allotment of time, I would request that hours have not been allotted, only days have been allotted. This morning the Speaker announced that the debate on the 29th will be only upto 4 p.m. It means that two hours have been reduced. So our proposal is—I discussed it informally with the Speaker also that tomorrow we may dispense with the lunch so that one more hour we can have and if the House agrees we can extend sometime on the 30th because almost 3-4 hours have been reduced and that way we can have a proper debate.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND COM-

MUNICATIONS (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): We have no objection.

MR. CHAIRMAN: The Speaker will take a final decision. Mr. Chandrakar.

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर (दुर्ग) : अध्यक्ष जी मैं आज यहां राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर श्री कृष्ण जी के धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए भाषण दे रहा हुं। यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में यह आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार आर्थिक विकास की ओर अधिक ध्यान देगी।

राष्ट्रपति जी के भाषण को मुख्यत: पांच भागों में बांटा जा सकता है। एक—समाज का अत्यन्त गरीब वर्ग जिसे कंगाल कहते हैं ह्वलो पावर्टी लाईन रहने वाला कहते हैं उसकी दशा सुधारने के लिए तत्काल कदम उठाए जायेंगे। दो–देश में अराजकता के युग को समाप्त करना। तीन—महगाई रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चार—देश की रीढ़ देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और पांच–अफगानिस्तान की स्थिति पर चिन्ता।

यह सही बात है कि पिछले ढाई वर्षों में भारत सरकार ने राजनीतिक जोड़ तोड की ओर विशेष ध्यान दिया और प्रशासन की ओर बिल्कुल नहीं के बराबर ध्यान दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि देश का आर्थिक विकास पूर्णत: ठप्प हो गया। इसी प्रकार के से देश में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। यह तो आज भूतपूर्व मंत्री श्री चरण सिंह के भाषण से भी जाहिर है क्योंकि उन्होंने जितना भी आज कहा उसमें इतना ही कहा कि इन्दिरा शासन के समय 11 वर्षों में अमुक अमुक चीजे नहीं हुई और बेरोजगारी बढ़ी आदि लेकिन ढाई वर्षों में जनता पार्टी या लोकदल की सरकार ने क्या क्या किया उसके एक शब्द की भी चर्चा नहीं की। इससे यह बात साफ है कि उनके सामने कहने को कुछ था ही नहीं।

आप जानते हैं ढाई तीन वर्ष पहले हमारे देश का लोहा और सीमेण्ट बाहर जाता था लेकिन इसी काल में दूसरे देशों से इस देश में लोहा और सीमेण्ट आने लगा। किसी भी देश के आर्थिक विकास की बुनियाद होती है सीमेण्ट, लोहा, कोयला, बिजली लेकिन इस देश में इन चीजों की अत्यन्त कमी हो गई। ऐसी स्थिति में कारखानों का उत्पादन बढ़े तो कैसे बढ़ जब कोयला, बिजली, डीजल और पेट्रोल न मिले। कारखानों को जब ईंधन ही नहीं मिलेगा तो उत्पादन कैसे बढ़ेगा? इसमें कोई शक नहीं है कि देश के मजदूरों ने देश के आर्थिक विकास में अपना पूरा सहयोग देने का प्रयत्न किया लेकिन जनता पार्टी और लोकदल सरकारों ने उनका सहयोग लेने से लगभग इनकार ही किया।

इसी तरह से पिछले ढाई वर्षों में पब्लिक सैक्टर के विकास के कामों में कुछ ऐसे कदम उठाये गये, जिन से पब्लिक सैक्टर बदनाम किया गया। आप देखिये—इस्पात के उत्पादन के लिए कोकिंग-कोल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में कोकिंग कोल की कमी जरूर है, लेकिन इतनी कमी नहीं है कि हम विदेशों से कोकिंग कोल मंगायें। यदि हम अपने ही देश में "वाशिंग-प्लांट्स" या "माशरीज" खोलें तो देश के कोयले से उस के "ऐश-कन्टेन्ट्स" को साफ कर के लोहे के उत्पादन के लिए कोयला उपलब्ध करा सकते हैं। लेकिन इस बात की उपेक्षा की गई और विदेशों से कोयला मंगाया जाने लगा।

जनता पार्टी की सरकार ने प्राय: देश के सभी कमजोर वर्गों की उपेक्षा की, चाहे वे खेतिहर मजदूर हों, कारखानों में काम करने वाले मजदूर हों सब्जी बेचने वाले हों मोची हों, रिक्शा चलाने वाले हों उन का विश्वास जनता पार्टी और लोकदल से बिलकुल उठ गया था और इस बात का सुबूत यह है कि मतदाताओं ने खास तौर से इस वर्ग के लोगों ने कांग्रेस के उम्मीदवारों का साथ दिया। इस का कारण यह था कि जनता पार्टी और लोक दल की सरकारों के समय में उन की उपेक्षा की गई। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जो इन्दिरा सरकार के समय में लागू किये गये थे इन वर्गों को जो लाभ होता था जिन के पास जमीन नहीं थी जो गरीब थे हरिजन थे आदिवासी थे उन को जमीनें दी जाती थीं बैंकों के द्वारा कर्ज दिये जाते थे चाहे मोची हो, रिक्शा चलानेवाला हो उस को बैंकों से ऋण की सहायता मिलती थी ये सब सुविधायें ढाई वर्ष के समय में पूर्णतया बन्द कर दी गई जिस के कारण गरीबों के विकास के सभी मार्ग बन्द हो गये। उस सरकार के प्रति इस वर्ग में बहुत ज्यादा रोष पैदा हो गया था और उस वर्ग ने अपना रोष पिछले चुनाव में इन पार्टियों को ला कर दिखाया।

इतना ही नहीं जनता पार्टी और लोक दल की सरकारों ने मंहगाई को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। यदि कुछ किया तो मंगहाई को बढ़ाने के काम को प्रोत्साहन दिया—यदि ऐसा कहा जाय तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। आप देखिये—पहले दुकानों में वस्तुओं के मूल्य लगाये जाने का नियम था, दुकानों में जितनी चीजें बिकती थी उन के मूल्य वहां लगाये जाते थे..

एक माननीय सदस्य : एमर्जेंसी के समय में।

श्री चन्दूलाल चन्द्राकर : एमर्जेंसी में या किसी भी समय में किया गया, लेकिन मूल्य लगाये जाने का नियम था। क्या मूल्यों का लगाया जाना कि अमुक वस्तु का मूल्य यह है—यह अन्याय है। यदि अन्याय है तो आप साफ-साफ कहिये कि अन्याय है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकेंगे..... (व्यवधान)..... चीजों के

मूल्य लिखने से या चीजों के मूल्य घोषित करने से किस को घबराहट होती है, इस नियम को रोक कर आप किस वर्ग को समर्थन देना चाहते हैं, किस को लाभ पहुंचाना चाहते हैं ? चीजों के मूल्य लिखे जाने से कोई भी गरीब से गरीब आदमी जाता था और उस को अमुक मूल्य पर वस्तु खरीदने का आश्वासन मिलता था । लेकिन इन ढाई वर्षों में क्या हुआ ? आप किसी भी चीज को लेने जाइये--गेहूं और चावल के दाम तो कम बढ़े, लेकिन अन्य चीजों के दाम इतने बढ़ गये जिस का कोई हिसाब नहीं । आप आज सबेरे कोई चीज खरीदने जाइये, उस के बाद कल सबेरे जा कर देखिये तो उस के दाम काफी ज्यादा या कुछ न कुछ अवश्य बढ़े हुए मिलते थे। पिछले 6 महीने या साल भर में चीजों के दाम कितने बढ़े--इस की चर्चा हमारे भूतपूर्व प्रधान मंत्री ने अपने भाषण में बिलकुल नहीं की । उन्होंने यह नहीं बतलाया कि उन के कार्यकाल में चीजो के दाम कितने बढ़े हैं, बेरोजगारी कितनी बढ़ी है । उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि अमुक-अमुक साल में इन्दिरा कांग्रेस के समय में इतने दाम बढ़े, लेकिन उन्होंने यह नहीं बतलाया कि पिछले ढाई सालों में कितनी मंहगाई बढ़ी । हमारे देश में पिछले ढाई सालों में बेरोजगारी निश्चित रूप से डेढ़ गुना या दो गुना अधिक बढ़ गई है । आप किसी भी इलाके में चले जाइये, किसी भी गांव में चले जाइये, हमारे देश में 5 लाख 75 हजार गांव हैं, प्रत्येक गांव में युवकों में बेरोजगारी की संख्या बढ़ी है और बढ़ती जा रही है । उन की हालत को सुधारने के लिए या काम देने के लिए पिछली सरकार ने 10 वर्ष का समय दिया था कि हम 10 वर्ष में बेरोजगारी दूर करेंगे । भला कब तक ये बेरोजगार इस का इन्तजार करेंगे । इसलिए 1980 के जो अभी चुनाव हुए हैं, उन से भी जो राज्यों में जनता पार्टी या लोकदल की या मिली-जुली सरकारें हैं, उन्होंने अभी तक कोई सबक नहीं लिया है । आप इस बात को इसी से जानिये कि चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे बिहार हो, चाहे राजस्थान हो और चाहे मध्य प्रदेश हो, या और भी राज्य हों, जहां भीषण अकाल है, वहां पर राहत कार्य नहीं खोले जा रहे हैं । आखिर किस लिए ? राहत कार्यों के लिए गरीब लोग काम चाहते हैं, मेहनत कर के पैसा कमाना चाहते हैं, वे मुफ्त में पैसा नहीं चाहते लेकिन फिर भी उन के लिए राहत कार्य नहीं खोले जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश के बारे में अच्छी तरह से जानता हूं । छत्तीसगढ़ से लगभग 6,7 लाख लोग रोजी-रोटी की तलाश में दिल्ली, शिमला और काश्मीर तक चले गये हैं । जो गर्म क्षेत्रों के रहने वाले हैं, वे भी ठंडे क्षेत्रों में काम करने के लिए आ रहे हैं। सिर्फ इसलिये कि उन को अपने यहां काम नहीं मिल रहा है और आज भी जनता पार्टी की सरकार चुनाव हारने के बाद भी किसी तरह का सबक नहीं ले रही है । अभी तक वह जनता के विरुद्ध अपना रवैया रखे हुए हैं और सबक लेने के लिए अभी भी तैयार नहीं है । इस में कोई शक नहीं है कि राहत कार्यों को खोलने का अधिकार राज्य सरकारों का है, उन को काम देने का अधिकार राज्य सरकारों का है और पीने के पानी की व्यवस्था करने का अधिकार भी राज्य सरकारों का है । सरकार कब तक इन गरीबों को भूखा रहने देगी और वे कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे । मुझे पूरा विश्वास है कि यदि एक बार यह प्रश्न उठे कि राज्य सरकारों को हटाया जाए या जनता को भूखा मरने दिया जाए, तो यदि आवश्यकता हो कि राज्य सरकारों को हटाया जाए, तो इस बात के लिए राज्य सरकारों को बर्खास्त करने के लिए सरकार को जरा भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए । लोग डेमोक्रेसी के नाम की कितनी दुहाई देते हैं लेकिन हर एक को यह मालूम है कि चिकमंगलूर से चुन कर जब श्रीमती गांधी सदस्य बनी थीं, तब उन को हटाने के लिए किस तरह की कार्यवाही की गई, उसका मैं यहां पर विवरण नहीं देना चाहता लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आप इस बात को देखिये कि आज मध्य प्रदेश की सरकार चुनाव में हार जाने के कारण इन्दिरा कांग्रेस को बदनाम करने के लिए जबरदस्ती नसबन्दी कई जगहों पर करवा रही है । जबर्दस्ती इसलिये की जा रही है क्योंकि लोगों ने इन्दिरा कांग्रेस को वोट दिया है । सरकार को इस बात की अच्छी तरह से समझ लेना चाहिये कि उन के इरादे क्या हैं ।

इस सम्बन्ध में मैं दो, तीन चीजों की ओर और आप का थोड़ा सा ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । एक बात तो यह है कि अफ़गानिस्तान की स्थिति के सम्बन्ध में निश्चित रूप से हमारे देश को भी चिन्ता है । अभी देश में इस बात पर संतोष है कि हमारे देश का प्रधान मन्त्रित्व आज श्रीमती इन्दिरा गांधी के हाथों में आ गया है लेकिन अगर जनता पार्टी या लोक दल के प्रधान मंत्री ऐसे समय में यहां होते, तो निश्चित रूप से हमारे देश के लोगों में उतनी चिन्ता बनी रहती जितनी पहले थी क्योंकि देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि दुनियां के तीन, चार बड़े नेता हैं जिनमें श्रीमती इन्दिरा गांधी का स्थान आता है और अफ़गानिस्तान की समस्या के साथ जो समस्या हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के और हमारे बीच में आने वाली है, हमको पूरा विश्वास है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस समस्या को शान्तिपूर्वक हल कर लिया जाएगा । इस में कोई शक नहीं है कि हमारे देश के मतदाताओं ने दूरदर्शिता से काम लिया है और इस देश को बचाने के लिए श्रीमती इन्दिरा गांधी को यहां चुन कर भेजा है।

मैं आप का और अधिक समय न लेकर केवल इतना ही और कहना चाहता हूं कि मतदाताओं का जो निर्णय है, उसको ध्यान में रखकर सरकार इस बात पर विचार करे कि केवल बदले की भावना से कांग्रेसियों पर जो मुकदमें चलाये जा रहे हैं, उन्हें तत्काल वापस लेने के लिए हमारी सरकार को भी कदम उठाने चाहिए ।

SHRI SAMAR MUKHERJEE (Howrah) : Mr. Chairman, Sir, the time at my disposal is not much.

MR. CHAIRMAN : 27 minutes for the whole group.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Yes, Sir. There is another speaker from our group. So, Sir, I want to deal with some of the very basic problems and I want to draw the attention not only of the House but of the people of the whole country to certain matters. A new Government has come into power, but, it has got a certain background and that is why the question of the past always comes into the picture and it comes into the discussion. I had read the speech of the President. I have seen the Election Manifesto of the ruling party. I have seen how for all the mischief done, they have laid the total blame on the government of the Janata party.

AN HON. MEMBER: And you.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Yes, you can include us. I am interested in placing this reality. But there is not the slightest self-criticism at all; there is nothing of that kind. You don't find a single self-criticism at all why in 1977 Indira Gandhi was thrown out of power. Not a single word is there. There has been no attempt on your part to learn from past why the people went against that Government. (*Interruptions*) Please don't disturb. I am speaking about this very seriously. Because, it has future implications. The Government, put into power by the people in 1971 has been thrown out of power in 1977. The same majority was got by this Government in 1971 but that Government was rejected by the very same people in 1977. So, something must have happened in between which might have antagonised the entire people of the country against this Government. (*Interruptions*) Our friend says, because of Marxist propaganda. Well, when thousands and thousands of people are put inside the jails, is it propaganda? When people were put to death behind bars like Rajan is it propaganda? When our friend Mr. Jyotirmoy Bosu was sent to Hissar Jail, is it propaganda? If you don't learn, then, you will have to face the same consequences. One day the same masses will throw you out. Please do not forget this. You are talking of democracy. Let us see what has happened. You have got just 43 per cent of the votes. 57 per cent of the people have voted against you. You say that the people who voted for you are alone the people but those who voted against you are not the people? Please learn what the reality is. These 57 per cent of people—who have very clearly refused to vote your party—are there. And whom do they expect to represent their causes? Whom do they expect to speak for them except the opposition? We may be numerically small, but the majority of the people are behind us. It is seen in the voting pattern. You have increased your percentage of votes by only eight per cent. In 1977 you got 34 to 35 per cent and this time you have got 42 to 43 per cent. The change is only an increase of 8 per cent of the votes and that too is because of the defective electoral rules and the system obtaining here. That is why you have got overwhelming majority of seats. That is because the opposition is divided. The moment the opposition is united you will be thrown out. (*Interruptions*). Sir, shouting cannot hide the real fact. (*Interruptions*).

MR. CHAIRMAN : Let the hon. Member proceed with his speech. You all will have ample time to reply.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : So, only a margin of 8 per cent vote was there. Mr. Chairman, I would like to draw the attention of the House to another thing. In 1971, what was the slogan given by Shrimati Indira Gandhi to the people? The slogan was *'garibi hatao'*. *'Garibi hat gaya'*. Unfortunately this is the understanding because Opposition has been removed, *'Garibi hat gaya'*. But the stark reality is poverty is increasing day by day. The cost of living is rising and I have all the facts before me. After 1971 elections, the income of the agricultural labourers has gone down.

The real income of the workers has gone down and on the other hand, the profit of the big monopoly-houses jumped. I have the list of 20 families. In 1966, Birla's assests were Rs. 475.86 crores. In March 1977, it went up to Rs. 1070.20 crores. In 1966, Tata's assests were Rs. 505.0 crores. In 1977, it was Rs. 1069.38 crores. In 1966, Mafatlal's assets were Rs. 92.70 crores. In 1977, it was Rs. 285.63 crores. All these things are given. (*Interruptions*) I do not defend the Janata Government We have opposed the Janata Government, you know. (*Interruptions*).

THE PRIME MINISTER (SHRIMATI INDIRA GANDHI) : Not at all. You have only supported their candidates. Where did you oppose them, I would like to know. (*Interruptions*).

SHRI INDRAJIT GUPTA (Basirhat): You supported the Janata Party in Kerala. For 27 seats you supported the Janata Party in Kerala just now.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : We have supported some Congress people. I would like to know whether those people you supported were Communists. But the ones we supported have been Congressmen. (*Interruptions*).

SHRI SAMAR MUKHERJEE : Mr. Chairman, one of our main complaints against the Janata Government is that they were pursuing the same policy which Shrimati Indira Gandhi has been pursuing in matters of economic policy. We supported the Janata Government only on condition of defence of democracy.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : Not at all.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Repeatedly we made it clear, you completely subverted democracy in 1975. (*Interruptions*). It is the people who have saved the parliamentary democracy by throwing you out and by putting the Janata Government in power. That is why the parliamentary democracy is here in existence today. (*Interruptions*). Mr. Chairman, our main criticism is against the Congress Government. Not only during the rule of 11 years of Shrimati Indira Gandhi but from the very beginning upto date the Congress Government has been pursuing a policy of capitalist development in India. That is why monopoly-houses are becoming bigger. Money is being concentrated in the hands of a few and poverty is increasing, unemployment is increasing and economic polarisation is growing and developing. That is why, more and more workers, peasants, poor men and employees have been forced to resort to agitation. The price rise cannot be checked. It is not a sin of the Janata Government alone, they have committed the same sin which your Government has committed in the past also.... (*Interruptions*). Do not talk of West Bengal.

PROF. MADHU DANDAVATE (Rajapur): The prices were under control in the first two years..... (*Interruptions*).

SHRIMATI INDIRA GANDHI: The Communist country of China is now depending completely on Western Europe.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : I am talking about basic policies. Please listen to my points.

SHRIMATI INDIRA GANDHI : I am listening very carefully.

SHRI SAMAR MUKHERJEE : As you are developing capitalism, your dependence on western capitalist countries is so much and it is increasing day by day. Now, there is a separate world, socialist world, they are very eager to extend their hand but because of your tie-up with all the big capitalist houses, your tie-up with America, the World Bank and the International Monetary Fund, you cannot free yourself from those links and tie-ups. I would like to tell you that your dependence more and more on the capitalist world will lead India to more and more economic crisis.

[Shri Samar Mukherjee]

They are unable to save their own country from the crisis and recession and that is why, to save themselves they are out to put the entire burden on you. Here, the multi-national corporations are given absolute freedom to loot our country; they are taking away crores and crores of rupees every year from our country and they are earning huge and unlimited profits. Your election funds are provided by these people, these big business houses, these traders and profiteers (*Interruptions*). And they want a return. When you are in power, they know, they would be able to get returns. Thus, there is no possibility of reversing the whole system. That is why as it has been mentioned in the President's Address if you want to reverse the course it requires a total and fundamental change in the entire system. But you cannot do that because of the way you are moving. You are tied up with all these capitalist and vested interests and its ramifications. The entire administration and the entire system is such that you cannot move any other way. Our apprehension is that it will further lead to more crisis there is deepening economic crisis as has been indicated here, and this is absolutely correct. I fully agree with this.

This situation is not only due to the two and a half years rule of Janata Government, but this is the total result of pursuing basically a capitalist policy since 1947 upto this day. You have declared your objective to have a socialistic system, but you are pursuing a policy to strengthen the capitalist system. What is socialism? In the world already there are so many countries who have built socialism and they have solved the basic problems of the people; there is no unemployment, no poverty, no price rise; you go and study Chinese economy. .... (*Interruptions*)

15.00 hrs.

MR. CHAIRMAN: Order, order. Let the hon. Member continue his speech.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Mr. Chairman, I have read out all these achievements in the last House, from literatures from almost all the socialist countries. There, in the Socialist countries there is the fundamental right to work, guaranteed by the Constitution. (*Interruptions*) You have given the fundamental right to property. You bring that amendment to the Constitution providing for the right to work as a fundamental right. (*Interruptions*)

AN HON. MEMBER: Shall we also accept Chinese democracy?

SHRI SAMAR MUKHERJEE: I do not want to argue with you about what is Chinese democracy, and what is your democracy?

Now about the question of stability. You have written that a stable Government has come into existence. Stability was there in 1971, but that stability had completely gone. Why was stability lost? Then, where is the guarantee that majority means stability? The majority may cross over any day, because political morality has come down to such a low level. Almost everybody is now purchaseable. This shows that the stability of various political parties is not there. (*Interruptions*) Can you deny, then; that there is a link between the economic crisis and the question of stability? There will be stability, if you can solve the economic crisis, if you can solve the problems of unemployment and of poverty. But if you pursue a capitalist system, the crisis is bound to accentuate further, and there will be no alternative before the people but to resort to the agitational path. Then the problem of law and order will arise. You will then start repressing. And after some time, the question of internal Emergency will come.

Here comes totalitarianism. The economic basis of totalitarianism is the exploitation of the economy by capitalist forces, national and international, and feudal exploitation. Unless they are removed, you cannot be the defender of democracy. Demo-

cracy means the rule of the majority. In our country, the majority are extremely poor and they are unemployed. Unless those basic problems are solved, no democracy can be stable. Keeping in mind the past record of this Government, I can say that when 57 per cent of the voters have voted against you, and only 43 per cent have voted for you, you should be modest. When you come to the Government anew, again, it is time to do rethinking about the entire system and your entire past. It requires an attitude of selfcriticism. You have sought our cooperation. On the one hand, you are seeking cooperation, but on the other you are organizing the toppling of all the State Governments outside. (*Interruptions*). This is the old policy we are acquainted with. Toppling was done in Kerala in 1959, by organizing *Vimochana Sangursh*. It is written in Moynilian's book that American money was given for toppling the Government. (*Interruptions*).

SHRIMATI INDIRA GANDHI: Mr. Chairman, may I have a word? This was contradicted by Mr. Moynihan himself when he was questioned at a Press Conference. He said that he did not mean that I got it. He said, "He thought."

SHRI SAMAR MUKHERJEE: I did not mention you.

SHRIMATI INDIRA GANDHI: But he said that the Party got it. (*Interruptions*).

SHRI SAMAR MUKHERJEE: He said, "Money had been taken by your Party".

SHRIMATI INDIRA GANDHI: But he had not been able to substantiate it in any way at all (*Interruptions*) Now he has been loudly protesting against American interference in this country.

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Another time money was taken in 1971 to topple CPI(M) Government in West Bengal so that they might not got elected. So, we know the background. Mr. Moynihan had given the money to your Congress.

AN HON. MEMBER: Where did you get the money?

SHRI SAMAR MUKHERJEE: Our money was collected from the people. Everybody knows about it. So, we know what toppling means. This is the background I am telling you. If you revert to that old past menthods, tactics, creating disturbances, asking the Governor to report that the law and order has failed and then toppling from the top by the order of the President, these methods we know. (*Interruptions*) So, democracy will not be strengthened. If you destabilise all the governments, your stability is bound to be affected. This is the relationship between destabilisation and your stabilisation. These are very hard words, I am to tell. I think you will give a thought to these things. Now you are starting a new Government. Whenever you do any good thing, we are prepared to cooperate with you. But the way you are going, it indicates that you are playing an old game and it will lead you to the same result which the earlier game had led you. That is why I warn this Government to be careful about all these things. You may feel elated after getting merely 43 per cent of the votes and 68-69 per cent of these seats. That is not the true reflection of the people's desire. We repeatedly demanded that there should be change in the electoral rules, there should be proportional representation and there should be right of recall. That is the real democracy.—But never it has been accepted. That is why, sometimes you are getting advantage. But when 57 per cent of the voters will unite, the entire advantage will go against you.

श्रीमती शीला कौल (लखनऊ) : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं। अभी कुछ बातें समर मुकर्जी साहब ने कही हैं। उन्होंने यह कहा कि अभिभाषण

[श्रीमती शीला कौल]

में यह जिक्र नहीं है कि कांग्रेस पार्टी क्यों हारी ? मैं तो यह सवाल पूछना चाहती हूं ढ़ाई साल में इन की पार्टी क्यों हार गई ? हमने तो काफी दिन तक काम भी किया। इन्होंने यह कहा कि जेल में लोगों को डाला गया इसलिए लोग नाराज थे । लेकिन इनके लोगों ने क्या किया कि जिन्दा लोगों की हड्डी का पिंजर बनाया, भूखा मारा । तो उनको क्या उम्मीद थी कि वह कैसे वापस आ सकते थे ? (व्यवधान)

अलफाजों के हेरफेर से समस्या का समाधान नहीं होता, आप को चाहिए कि सरकार के साथ बैठ कर अपनी राय दें और उस पर काम करें । यह कहना कि कानून-व्यवस्था खराब होती जायगी--मैं अपने उन दोस्तों से कहना चाहूंगी--अगर वे ईमानदारी से हमें सहयोग दगे तो फिर कानून-व्यवस्था क्यों खराब होगी । ये कुछ ऐसी समस्यायें हैं, जिन में हमारे जो अपोजीशन के साथी है, उन की मदद बहुत जरूरी है और अगर वे इस पर ध्यान देंगे, सहयोग देगें तो हमारे सामने जो भी समस्याय हैं उन को हम आसानी से दूर कर सकेंगे ।

हमें मालूम है--आज बहुत सारी राष्ट्र विरोधी शक्तियां हमारी सीमा पर इस समय सक्रिय हो गई हैं। ऐसे समय में हमारे देश की अखण्डता और एकता का होना बहुत जरूरी है। मैं आप को याद दिलाना चाहती हूं--हमारे पड़ौस का जो हिन्दुस्तान का सब से बड़ा प्रान्त है--उत्तर प्रदेश--वहां जनता की आज क्या हालत है ? वहां दिन-दहाड़े डकैती, चोरी, राहजनी, बहनों और बहुओं की इज्जत को खतरा बना रहता है । हमारी बहुएं जो कम दहेज ले कर आती हैं उन को किसी न किसी बहाने से जला दिया जाता है । उत्तर प्रदेश में कानून और व्यवस्था दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है । मंहगाई का जो इण्डेक्स है, वह इतना ज्यादा बढ़ गया है कि गरीब और मामूली हैसियत का आदमी भी कायदे से खाना नहीं खा सकता है । हमारी जो फैक्ट्रीज हैं, जो हम ने विरासत में ली हैं, आधी बन्द हैं और आधी लंगड़ा कर चल रही हैं । कुछ ऐसी हैं जिन में बहुत कम उत्पादन हो रहा है । बहुत सारी फैक्ट्रीज से हमारे वर्कर्स को निकाला गया है । इस से पहले कि हम बेरोजगारों के लिए कुछ करें उन को नौकरी देने की व्यवस्था करें, जो पहले से नौकरी में हैं, उन को भी नौकरी से निकाला जा रहा है ।

यदि आप किसानों की समस्या को लें तो वहां सीमेंट नहीं है, डीजल नहीं है, मिट्टी का तेल नहीं है । हमारे यहां जो सूखा पड़ा है, उस ने तो हमारी हालत को बहुत ज्यादा खराब कर दिया है । जब भी कोई सूखे की स्थिति पैदा होती है--उन समय ऐसी व्यवस्था की जाती है कि जो नहर खोदी जाती हैं, उन नहरों के जरिए पानी दिया जाता है । लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहां उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऐसी कोई कोशिश नहीं की कि नहरों के जरिए किसानों को पानी दिया जाय। मैं आप के सामने एक उदाहरण देना चाहती हूं--लखनऊ क्षेत्र में एक स्थान है--चिनहट, जहां "बिस्तौली" की माइनर इरिगेशन कैनाल है, डेढ़ साल से उस नहर में पानी नहीं दिया गया । ये लोग कहते हैं कि हम किसानों के दोस्त हैं, किसानों की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं--यह उन के काम का नमूना है । अलफाज से दुनिया नहीं चलती है, जब खुद काम करेंगे तब दुनिया चलेगी । इस वक्त तक वहां किसानों को पानी नहीं दिया गया है, सब तरफ सूखा पड़ा हुआ है ।

बेरोजगारी की हालत को भी देखिए--मुझे याद आता है, डेढ़ साल पहले, इन्हींके लाॅ-मिनिस्टर ने कलकत्ते में कहा था कि चार करोड़ लोग और बेरोजगारों में आ गये हैं । ये इन के अपने फेक्ट्स एण्ड फिगर्स हैं, हमारे नहीं हैं । जब कानून और व्यवस्था का जिक्र आता है तो मैं आप को बतलाना चाहती हूं--हमारे यहां जो युवक हैं, छात्र हैं, वे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें न मिट्टी का तेल मिलता है और न बिजली मिलती है । बिजली की कटौती इतनी सख्त है कि बच्चे न सुबह पढ़ सकते हैं और न रात को पढ़ सकते हैं । जब बच्चे नहीं पढ़ सकेंगे--हमारा और आप का लड़का नहीं पढ़ सकेगा--तब फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ? यही होगा कि वह लाॅ-एण्ड-आर्डर को अपने हाथ में लेगा । इसी मांग को ले कर लखनऊ में जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां के छात्रों ने असेम्बली के सामने धरना दिया, वहां उन को पीटा गया । यह 23 जनवरी की बात है, वहां इन लड़कों का, महिलाओं का पीटा गया । इस लिए मैं आप से कहना चाहती हूं--और कहीं की सरकार जाय या न जाय, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार तो अवश्य जानी ही चाहिए । वहां के हालात इतने खराब हो गये हैं कि वहां की सरकार अब अपने आप को चला नहीं पा रही है । यही नहीं, गोंडा के कुछ छात्रों ने जब संस्कृत के लिए मांग की कि हमारे यहां संस्कृत होनी चाहिए, तो उन छात्रों को भी पीटा गया । तो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो छात्र हैं, वे उत्तर प्रदेश सरकार के खास टार्गेट बने हुए हैं । क्या वजह है, यह नहीं मालूम लेकिन छात्रों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वह इन-ह्यूमेन किस्म का हो रहा है ।

मैं तो यह चाहूंगी कि सब से पहले जो मैं ने बेरोजगारी का जिक्र किया है, उस की तरफ ध्यान दिया जाए और हमारे जो नौजवान हैं, उन्हें कोई न कोई काम दिया जाए और पढ़ाई का जो इन्तजाम है, उस को ठीक किया जाए । हमारे राष्ट्रपति जी ने अपने भाषण में इसी बात पर ध्यान दिया है और इस के लिए मैं

उन की बहुत आभारी हूं और म उम्मीद करती हूं कि आने वाले दिनों में हमारे लोगों की हालत बेहतर होगी ।

इन शब्दों के साथ मैं समाप्त करती हूं ।

श्री जगजीवन राम (सासाराम) : सभापति जी, राष्ट्रपति जी का भाषण और उस पर बहस एक ऐसा मौका है जब उन मुद्दों को ले कर सदन में राजनीति का अखाड़ा नहीं बनना चाहिए । राष्ट्रपति का आसन बहुत ऊंचा है और राष्ट्रपति के भाषण को हम को उसी दृष्टि-कोण से देखना चाहिए और उसी दृष्टिकोण से उस पर बहस करनी चाहिए । राजनीतिक दांव-पेंच करने के तो बहुत मौके होते हैं और इस सदन में भी बहुत मौके आया करेंगे । मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति के भाषण को उस तरह से इस्तेमाल करना उचित नहीं हुआ । राष्ट्रपति को तो दिशा-निर्देश देने का अवसर होता है ।

जब नई सरकार आई, मैं इस बात को मानता हूं कि देश से एक नया आदेश लेकर आई, एक नया मैनडेट ले कर आई । मैं उस चीज में जाना नहीं चाहता कि आप को कितने प्रतिशत वोट मिले । वे आंकड़े तो उछाले जाते रहेंगे, मैं उनको उछालना नहीं चाहता क्योंकि मैं इस बात को मानता हूं कि जब तक हमारे निर्वाचन की पद्धति वैसी है जैसी कि आज है, तब तक जनता की ख्वाहिश प्रतिबिम्बित होती है कि जनता ने आप के कितने प्रतिनिधियों को लोक सभा में भेजा है । मैं जनता के उस निर्णय के सामने सिर झुकाना ही पसन्द करता हूं । राष्ट्रपति जी से जो आप ने कहलवाया, उस में से अगर कुछ अंश न कहलवाए जाते, तो राष्ट्रपति जी की गरिमा अक्षुण्ण रखी जाती । मैं फिर भी उस में जाना नहीं चाहता और मैं उस गरिमा को कमजोर भी करना नहीं चाहता हूं लेकिन एक बात तो जरूर कहूंगा कि आप ने जितने कार्यक्रम राष्ट्रपति जी से कहलवाए हैं, भारत का कोई भी राजनीतिक दल होता, वह इन कार्यक्रमों को कहलवाता ही है । 'गरीबी से लड़ना है, बेकारी को दूर करना है, असमानता को मिटाना है, पैदावार को बढ़ाना है ।" कौन सा राजनीतिक दल होगा, जो इन बातों से मतभेद रखेगा या राष्ट्रपति से ऐसा नहीं कहलवाएगा । लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि आप ने जो यह दिशा-निर्देश दिलवाया है, उस को आप कैसे पूरा करने जा रहे हैं ? क्या जो सामाजिक परम्परा आज है, उसका ही रख कर ऐसा किया जा सकता है । उस तरफ आप का कोई ध्यान नहीं गया । क्या आज जो आर्थिक व्यवस्था चल रही है, उस को कायम रख कर गरीबी मिटा सकते हैं ? उस तरफ कोई भी निर्देश नहीं गया । क्या विषमता मिटाने के लिए पदावार बढ़ा कर के ही उसको मिटा सकते हैं ? पैदावार तो बढ़ती गई है लेकिन साथ ही साथ गरीबी भी बढ़ती गई है । इसलिए कहीं न कहीं कुछ कुण्ठा है, कहीं न कहीं कोई अवरोध है । उस की तरफ काई प्रकाश राष्ट्रपति के भाषण में नहीं डाला गया है । आशा थी कि नयी सरकार कुछ नयी रोशनी लेकर आयेगी । लेकिन बे ही गलियारे वैसा हीं अंधियारा जैसा कि पहल था । (**व्यवधान**) यह तो आंखों पर निभर करता है कि यह कम हुआ या नहीं हुआ । जैसा मैं ने प्रारम्भ में ही कह दिया है कि राजनीतिक दाव-पेच और पार्लिया-मेंटरी स्किल (Parliamentary Skill) के ढंग से तो बहुत सी बातें कही जा सकती हैं और कहना मुझको भी आता है लेकिन मैं इस मौके पर उसको कहना नहीं चाहता ।

मैं इस से सहमत नहीं होता कि कांग्रेस ने तीस वर्षों में कुछ नहीं किया । लेकिन अगर देखने की इच्छा न हो या देखने का हुनर न हो तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता है । ठीक उसी तरह से यह कह देना कि जनता पार्टी द्वारा ढ़ाई वर्ष में कुछ नहीं किया गया, वह ऐसी ही बात है । (**व्यवधान**) यह तो इस पर निर्भर करता है कि बर्बादी किस तरह से की जाती है । और बर्बादी क्या होती है । इसके लिए भी आंखों की परख होती है । कौन इस बात से इंकार करेगा कि इन दो-ढ़ाई वर्षों में पर-केपिटा इनकम नहीं बढ़ा । मैं इनमें विस्तार में नहीं जाना चाहता । इसके आकड़े हैं, आप आंकड़े देख लीजिए । अगर आपको लग कि इन ढ़ाई वर्षों में कुछ नहीं हुआ तो मैं भी आपके साथ सहमत हो जाऊंगा । अगर आंकड़े कहें कि तरक्की हुई है तो यह ईमानदारी का तकाजा है कि आप उनसे सहमत हो जाएं ।

मैं यह कहने के लिए भी खड़ा नहीं हुआ हूं कि उस दौरान सब कुछ हो गया । खामियां रही हैं लेकिन खामियां सभी सरकारों में रहेंगी क्योंकि हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था इस तरह की है कि जब तक उसमें आमूल परिवर्तन हम नहीं कर लेते तब तक अपनी समस्याओं को हम सुलझा नहीं सकते । इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है ।

मैं आप से इस बात को भी कह रहा हूं कि आप एक बड़े कदम के साथ, बहादुरी के साथ आगे आयें और कहें कि हम परम्पराओं को तोड़ने जा रहे हैं और आप कहें कि हमारी जो वर्तमान आर्थिक व्यवस्था है उसको लेकर हम गरीबी को नहीं मिटा सकते । अगर आप यह सही माने में कहें तो आपके साथ हमारा सहयोग होगा । क्योंकि यह समस्या केवल शासन करने वालों की ही नहीं है । यह समस्या देश की समस्या है । इस समस्या को सुलझाने का क,म हम सिर्फ आप पर छोड़ कर आपका उलाहना देते रहें ता इस पर भी मैं विश्वास नहीं करता । काम इतना महान् है, इतना जटिल है । लोग गरीबी के नीचे कराह रहे हैं उनको देख कर सिर शर्म से झुक जाता है । यह सुन कर सिर शर्म से झुक जाता है जब दूसरे यह कहते

[श्री जगजीवन राम]

हैं कि हमारे देश में करोड़ों आदमी ऐसे हैं जिनकी आमदनी आठ आन रोज भी नहीं है। इसलिए इसके लिए सरकार को उलाहना देने से काम नहीं हो पाएगा। इस काम में हम सभी का कंधा लगाना है।

जनता पार्टी ने एक परम्परा कायम की है विरोध पक्ष को आदर देने की। मैं नहीं कहता कि आप ही आदर दें लेकिन मैं यह जरूर कहता हूं कि आप सहयोग की कामना करें। अगर सही मायनों में सहयोग की कामना होगी तो इस तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सहयोग देने में कोई कोताही नहीं की जाएगी। (**व्यवधान**) परम्परा को परखने की भी आदत होनी चाहिए। इसलिए मैं आपसे यही कहने के के लिए खड़ा हुआ हूं। बात तो देश की और बाहर की बहुत कहनी हैं लेकिन मैं अपने साथियों के लिए भी समय छोड़ना चाहता हूं।

अफगानिस्तान में जो हो रहा है, वह सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, दुनिया के लिए भी चिंता का विषय बन गया है। वहां ज्वालामुखी भभक सकता है। अगर वह भभकेगा तो उसकी लपटों से भारत बच नहीं सकता असम में जो कुछ हो रहा है, वह किसी भी देश के लिए चिंता का विषय हो सकता है। (**व्यवधान**) जिम्मेदारियां बांट देने से तो काम नहीं हो जाता कि जनता पार्टी न कसूर कर लिया और वहां आग भड़क गयी। यह कहने से तो मामला खत्म नहीं हो जाता। यह तो हमारे और आपके दोनों का मामला है। असम भारत का अंग है। सारा पूर्वोत्तर भारत आज ज्वालामुखी के मुख पर बैठा हुआ है। उसको सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी कह कर नहीं टाला जा सकता। अगर आपकी गल्तियों से सारे देश का यह हिस्सा अलग होता है तो वह आपका ही हिस्सा अलग नहीं होता है, सारे भारत का हिस्सा अलग होता है। इसलिए इसमें हमारी और आपकी दोनों की शिरकत होनी चाहिए। जो परिस्थितियां वहां पैदा हो गयी हैं वे बहुत जटिल हैं, आसान नहीं हैं। यह कह देने से काम नहीं चल सकता कि उनको हम कहीं भारत में बसा देंगे जो नाजायज तरीक से असम में आ गये हैं। उनको हम भारत में कहीं बसा देंगे। भारत का हर प्रांत परेशान है। आप कहां बसायगे ? खैर, इसमें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि देश के भीतर और बाहर ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं जो किसी भी देश क लिए कठिन समय पैदा कर सकती हैं। अफगानिस्तान के मामले में हमें बहुत फक फूंक कर बोलना पड़ेगा, समझ कर बोलना पड़गा, तौल कर बोलना पड़ेगा, एक एक शब्द का तौल कर बोलना पड़ेगा, इसलिए कि अफगानिस्तान जो आज दुनिया की बड़ी-बड़ी शक्तियों का अखाड़ा बन रहा है, उन शक्तियों के अखाड़े का असर हमारे ऊपर न पड़ जाए, हम उन से कसे अपने आप को बचा सकते हैं, इसके लिए बहुत सावधानी और सतर्कता की आवश्यकता होगी। चाहे मणिपुर का प्रश्न हो, नागालैंड का हो, मिजोरम का हो, एक-एक प्रश्न देश को परेशान करन वाला प्रश्न बन चुका है। वहां के लोगों की कसे भारत के साथ एकरूपता कायम की जा सकती है, कैसे हम उनको परख सकते हैं और वे हम को परख सकते हैं, इस चीज को सोचने की जरूरत है। इस सब के बारे में आपको ही नहीं, हम को और आपको, दोनों का मिल कर सोचने की जरूरत है क्योंकि इससे राष्ट्र को खतरा पैदा हो सकता है। इन चीजो की तरफ मैं आपका ध्यान दिलाने के लिए खड़ा हुआ था, आलोचना करने के लिए नहीं। मैं भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण क एक-एक अनुच्छेद को ले कर उस पर टिप्पणी कर सकता हूं लेकिन आज करना नहीं चाहता। मैं भी बता सकता हूं कि क्या क्या खामियां हैं उस में लेकिन वह करना नहीं चाहता। मैं तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो वाद-विवाद हो रहा है उसका. . . ऊंची सतह पर रखना चाहता हूं, उसको राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहता। मेरा निवेदन है कि आप देखें राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कुछ आपने कहा है क्या वह परम्पराओ से कुछ अलग है ? अगर उन्हीं परम्पराओं पर चलना है तो मैं यही कहूंगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जो कुछ आपने कहा है वह एक पायस विश (अच्छी कल्पना मात्र) है, और कुछ नहीं।

श्री ए० नीललोहितदासन नाडार (त्रिवेन्द्रम) : सभापति महोदय, जो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। हमारी सरकार ने राजनीतिक स्थिरता लाने का, कानून और व्यवस्था को कायम करन का, दामों पर नियंत्रण लान का, अन्तर्राष्ट्रीय मामलों में सजीव सहयोग की जो बातें कही थीं, उनकी वजह से जनता ने इसको वोट दिया और इसको सत्तारूढ़ किया। श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में अखिल भारतीय कांग्रेस ने जब चुनाव के क्षेत्र में कूदने का फैसला किया तो जनता के सामने एक चुनाव घोषणा पत्र रखा था। इस चुनाव घोषणा पत्र में जो बातें कही गई थीं, और जो कार्यक्रम बताए गए थे उन्हीं के आधार पर, उन पर विश्वास करक जनता ने हमें वोट दिया और हमें सत्तारूढ़ किया। इसलिए हर क्षण हमें इस बात का सवक्षण करते रहना चाहिए। कि उस चुनाव घोषणा पत्र में जो कार्यक्रम बताए गए हैं उन्हें पूरा करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, उनको लागू करने के लिए हम कौन से पग उठा रहे हैं और उन लक्ष्यों को जो उस में बताए गए हैं, प्राप्त करने में हम कहां तक सफल हुए हैं। मैं समझता हूं कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को भी हमें चुनाव घोषणापत्र के संदर्भ में, उसकी पृष्ठभूमि में देखना चाहिए और उसकी जांच करनी चाहिए।

हमारे चुनाव घोषणापत्र में जो जो कार्यक्रम बताए गए हैं उन में से बहुत से कार्यक्रमों का जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी किय गया है। इसलिए मैं उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहन

चाहता। चुनाव घोषणापत्र और राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की तुलना करने पर जो कमियां मैं पाता हूं उनको दृष्टि में रखते हुए मैं कुछ बातें आप की सेवा में निवेदन करना चाहता हूं।

चुनाव घोषणापत्र के दसवें पैरा में जनता पार्टी के शासन के दोषों की ओर ध्यान दिलाया गया है। । इन में कहा गया है कि धर्म निरपेक्ष पुस्तकों का वापिस ले कर उसके स्थान पर सम्प्रदायिकता भरी पुस्तकों को लाया गया और ऐसा उसने एक एग्जैक्टिव (executive) आर्डर के जरिये किया। लेकिन हमारी सरकार ने 14 दिन के बाद भी एक ऐग्जीक्यूटिव आर्डर के जरिये साम्प्रदायिकतावादी पुस्तकों की जगह धर्मनिरपेक्ष पुस्पकों को लाने का अभी प्रयास नहीं किया है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस काम को जितनी जल्दी कर सके उतना जल्दी करे।

हमारे चुनाव घोषणापत्र के 13 वें पृष्ठ में कहा गया है:

"Full utilisation of licensed capacity in all sectors will be ensured by insistence on drastic efficiency measures."

लेकिन राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में कहा गया है:

"On the industrial front, emphasis will be laid on the rapid increase in industrial production through better utilisation of the existing capacity."

मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि लाइसेंस कैपेसिटी में और ऐग्जिस्टिंग कैपेसिटी में काफी फर्क है। लाइसेंस कैपेसिटी हम अपनायें तो लाइसेंस जब सरकार देती है उसी समय सरकार जितना उत्पादन करने की अनुमति देती है उस अनुमति के अनुसार ही उद्योगपति (इंडस्ट्रियलिस्ट) उत्पादन कर सकता है। लेकिन ऐग्जिस्टंग कैपेसिटी में तो उद्योगपति अपनी इच्छानुसार उत्पादन कर सकते हैं और अधिक लाभ उठा सकते हैं। इसलिए ऐग्जिस्टिंग कैपेसिटी वाले शब्द अगर रहे तो मल्टी नेशनल्स और मानोपोलिज पीछे के दरवाजे से आगे कूद पड़ते हैं और राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में अपना प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि ऐग्जिस्टिंग शब्द बदल कर लाइसेंस्ड कैपैसिटी शब्द जोड़ दें। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो कम से कम प्रधान मंत्री जी को इसका क्लैरिफिकेशन देना चाहिये।

बच्चों और नौजवानों के लिये कोई कार्यक्रम का जिक्र राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में नहीं किया गया है सरकार को स्पष्ट करना चाहिये कि भूमि सुधार वाले कार्यक्रम राज्य सरकारों के जरिये कैसे लागू करायें जायेंगे। मेरा मत है कि भूमि हीन लोगों की कमेटी ताल्लुक, और ब्लाक लेविल पर बना कर भूमि सुधार कार्यक्रम राज्य सरकारों द्वारा लागू करने के लिये केन्द्रीय सरकार को जल्दी ही निर्देश देना चाहिये।

दामों का नियंत्रण करने या मंहगाई को रोकने की समस्या हमारे लिये बहुत ही कठिन बन गयी है। सारे देश भर में एक आम पद्धति लागू करनी चाहिए इसके अतिरिक्त जो तस्करों और कालाबाजारियों और जमाखोरों जैसे समाज विरोधी तत्वों पर मुकदमें चलाने के लिए विशेष अदालतें (स्पेशल कोर्ट) का गठन करना चाहिए।

किसानो के लिए क्रोप इन्शोरेंस (Crop Insurance) स्कीम के बारे में हमारे चुनाव घोषणा पत्रों में कहा गया है। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में कुछ नहीं कहा गया है। मेरा निवेदन है कि सरकार को क्रोप इशोरेन्स स्कीम को लागू करना चाहिए।

हमारे मछुओं की समस्याओं को गम्भीरता पूर्वक देखना चाहिए। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी हमारे मछुओं के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। मध्यवर्ती (मिडिलमैन) के शोषण से मछुओं को बचाना चाहिए। डीप सी फिशिन्ग के लिए मल्टीनेशनल्स को जो अनुमति दी गई है उसको वापस लेना चाहिए। मल्टीनेशनल्स का डीप की फिशिंग से दूर रखना चाएहि। मछुओं के बच्चों के लिए और उनके परिवार के लिए एक ग्रास प्रोग्राम को अपनाना चाहिए जिसके जरिए उनके बच्चे फिशरीज और उससे सम्बन्धित उद्योगो को अपने आप लागू कर सकें और उसका प्रशिक्षण उनको दें।

हैंडलूम वीवर्स आर्टिजान्स और अन्य हैन्डी क्राफ्टस मजदूरों की समस्याओं पर भी काफी ध्यान देना चाहिए। और उनको भी मध्यवर्ती लोगों के शोषण से बचाना चाहिए।

हमारे चुनाव अभिभाषण में 19वें पेज (age) पर कहा गया है:—

"Congress proposes that at least one adult member per family is employed at socially acceptable wage level within a time-bound programme. Constitutional constraints on the scheme, if any, will be sorted out."

लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। मेरी प्रार्थना है कि प्रधान मंत्री अपने भाषण में इस के बारे में सरकार की नीति को स्पष्ट करें।

केरल एक छोटा सा राज्य है जो अधिक राजनैतिक प्रभाव नहीं डाल सकता है। जा जनता पार्टी का शासन हो चाहे लोक दल का शासन हो और चाहे कांग्रेस का शासन हो केरल की समस्याओं को और अधिक ध्यान नहीं दिया

[श्री नीललोहितदासन नाडार]

गया है । इस लिए अब यह आवश्यक है कि केरल की समस्याओं पर विशेष ध्यान दे कर उसके आर्थिक तथा औद्योगिक विकास के लिए कदम उठाया जाय ।

हमारी जनता सब कुछ जानती है । वह इधर या उधर बैठे हुए सदस्यों से अधिक जानती है । वह जानती है कि कब क्या करना है । जनता ने 1977 में जो कुछ किया और अब जो कुछ किया उससे पता लगता है कि वह सब कुछ जानने वाली है । आज हमारी जनता के लिए प्रजातंत्र एक जीवन शैली बन गई है । जनता को प्रजातंत्र का पहला पाठ हमारे महान नेता पंडित जी ने दिया था । पंडित जी ने जनता को यह सिखाया था कि प्रजातंत्र एक राजनैतिक स्ट्रेटेजी ही नहीं है वह एक जीवन शैली है । इसी लिए प्रजातंत्र हमारी जनता के लिए एक जीवन शैली बन गई है । हमारे चुनाव घोषणा पत्र में जो बातें कही गयी हैं उन बातों का क्रियान्वयन हमारा ध्येय और कर्त्तव्य होना चाहिए ।

इन शब्दों के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण में हमारे चुनाव घोषणापत्र में जो अच्छी बातें कही गई हैं उनके लिए मैं राष्ट्रपति को और सरकार को धन्यवाद देता हूं और जो धन्यावाद प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं ।

SHRI AMRIT PATEL (Gandhinagar): Mr. Chairman, Sir, I rise to support the Motion of Thanks on the President's Address.

Before I discuss the details and the points of the Address by the President, I am remind by the hon. Members from the Opposition of the responsibility towards this document. I assure them that we on this side also understand and appreciate the great importance that we attach to the President's Address. I will not take this opportunity to enumerate the deeds or the misdeeds of the previous Government of the Janata Party and the Lok Dal Party. But while confining myself to the Address of the President if I find some of their misdeeds, I hope, you shall excuse me.

Firstly, I would like to see the concern of the President which he states in his Address. He says:

> "The result of the election has made it possible for the country to look forward to a period of stable government at the Centre."

Now, when we discuss about a stable Government, Sir, the greatest concern of the President was stability because the President saw only, during the last two and a half years, a totally instable Government and a totally irresponsible Government. In the circumstances, his address was confined mainly stability.

This also brings me to the fact that whenever we require a stable Government, it can be formed only with a stable leadership, and a stable leader, requires certain virtues. If the leader has no such virtues, it is not possible for the Government to function.

The brings me back to some remarks of the great Winston Churchill wherein he has mentioned that one must be brave, that one must be resolute. I can assure you, Sir, that the Leader of my Party, Mrs. Gandhi is the bravest person, and I can also assure you that, Sir, she is the most resolute person in terms of executing the ideas of this Government. Through you I would like to assure the Hon. Members of the Opposition that we shall be magnamimous in dealing with the problems of the country. We are not here just to insult them Sir. Therefore, when the Hon. Member of the Opposition, Babuji, mentions our responsibility, we appreciate him, but I remind him that we can also do the same thing in our own capacity.

Now, stability has been talked about so much but, at the same time, there are other points discussed in the President's Address. I will confine my address also to the points in that address. I do not want to hear from others and I do not want others to tell us that we are talking beyond that Address. That is not our purpose. But our President was himself concerned in a great way, in a big way, about the misdeeds of the past Governments, and therefore I refer to another sentence: "The economic situation which the present Government has inherited....". The word

'inheritence' is not a small word. I need not remind the learned Hon. Members on the other side what we have inherited from them. Have we interited stocks of food or stocks of foreign exchange or of diesel or petrol? No Sir. When he mentions about interitance of an economic situation, it is the gravest, the rottenest situation given to us at this juncture which is the inheritance from the Opposition Parties. Under the circumstances, we must tell them or remind them that while we are dealing with the problems of this nation, we also warn them that they should cooperate with us in tackling the problems. At the same time, I would request them, through you, not to ignore the superior will of the voters. I repeat the words 'superior will' because there are so many Hon. Members on the opposite side who assume to themselves a lot of superiority. But that superiority is not confined to themselves. We know that the voters of this country have been totally superior.

It has been my experience, in my own constitutency, that whenever I go to small villages or small working classes. I find they are the most responsible people I have come across. They are concerned with the problems of the nation and they have been telling us that they are concerned about a stable Government. Therefore, I pass on this message to this august House, that we must have stability.

Regarding the 'massive mandate', the words gladden our hearts on this side of the House and sadden the hearts of the Opposition. I cannot help them if their hearts have been saddened because they do not have a majority. But we are not satisfied with the words 'massive mandate': we are concerned with the massive responsibility I am sure that through the leadership of our leader Mrs. Gandhi, we shall be very, very responsible in regard to the purpose for which we have been sent here.

Now I come to 'deal'. Again I remind that, in the year 1977. the Janata Party had the massive mandate. And what had they done? Again I am confining myself only to the President's Address. What had they given? They had given only a raw deal to the people of this country, the raw deal that had been given to the people and which made them suffer for two and a half years will not be pardoned in the history of India. As against the 'raw deal', I would like to speak on what is known as the 'New Deal'. The term 'New Deal' was coined in 1930s when the great United States was passing through economic depression. That was the time when a great leader was born, that is, President Roosevelt. He had looked after the details of only the economic problem of that country. Without making him smaller, I would now like to say that the Leader of our Party, Shrimati Indira Gandhi, has now to solve not only the economic problem which is the result of the Janata Party and the Lok Dal rule but also the problem of political instability. It is a great responsibility, a great task, on our Party and on our Leader, but I assure the Members on behalf of my Party that we will be able to go through all our responsibility.

Again I remind my learned opposition Members not to ignore or underestimate the superior will of the voters. They know exactly how our Party under the leadership of Shrimati Indira Gandhi is going to govern and what results we can bring.

With these words, I conclude.

SHRI C. T. DHANDAPANI (Pollachi): Sir, at the outset, the President of India has portrayed the misdeeds of the previous Governments, the desire of the present Government and the programmes which are going to be implemented in future. The people voted for Mrs. Indira Gandhi with one mind, with one voice, and with determination; they wanted one leader, that is, Shrimati Indira Gandhi.

It has been stated here that much damage had been perpetrated during

[Shri C. T. Dhandapani]

the last 33 months of Janata and Lok Dal rule—it has been reported in the press; I would like to place it before the House—in all spheres, economic as well as political. The common consumers' interests have been affected. The growth data has shown that there was a considerable downfall in production. It has been stated that there was a downfall in 1977-78 to the extent of 7.2 per cent and in 1978-79 to the extent of 4.5 per cent. Even the target of five per cent growth could not be achieved. That also went down to 3.4 per cent. Also a drop in the production of mass consumption goods has been recorded: as far as cotton fabric is concerned, the production has gone down by 7 per cent, sugar 30 per cent, tea 9 per cent, vanaspathi 7 per cent. In the same way the production of other commodities also has gone down considerably due to lack of proper management, as the President has stated correctly in his Address. Even after the presentation of the Budget, in 1979, the wholesale price had gone up by six per cent. After the presentation of the Budget in July, in one month alone it rose by 1.5 per cent; every month it had gone up by 1.5 per cent. No other place in the world recorded such a price increase which had taken place here; every week, the price rise was 1.3 per cent. A considerable deline in the income of labourers and agriculturists was also recorded. The purchasing power of the masses was considerably reduced. The poor and the middle classes were not able to purchase the food articles and other essential commodities.

I am thankful to the President for his remarks about the present government's endeavour to ensure proper remunerative prices to the farmers for their products. Remunerative prices are not being given to the agriculturists. For example, in my State of Tamil Nadu the Agriculturists' Association have demanded more remunerative prices. They put forth their demand before the have formed an Association and have State Government. The State Government have also sometimes assured them remunerative prices but they could not get it. They put forth a nine point programme before the State Government. Instead of looking into their demands the State Government is trying to suppress their movemet. You know the conditions of the agriculturists. They have no money because they could not get a proper price for their produce. At the same time, they got loans from the government. The government loans could not be repaid by them for the simple reason that the agriculturists are in trouble. They are not in a position to repay the loans and their demand was that the loans be written off because of the calamities and because their seasonal produce could not fetch them proper price. You know what the State Government did. They suppressed the movement. They killed many people. At the same time, they foisted many cases. More than 1000 people were arrested under Sec. 307. Their leader Mr. Narayanaswamy Naidu was arrested and a false case was foisted on him. A ban was imposed on him that he should not talk from any platform. Even now the ban is there. Has any political ally of the AIADMK lifted its little finger against this unjust ban? Mr. Narayanaswamy Naidu is pleading with the Central Government to intervene in the matter and do justice to his demand.

Here I want to tell something about the former Prime Minister, Choudhary Charan Singh. He made a reference about the alliance between our DMK party and the Congress Party. I do not want to say anything about the former Prime Minister because he is an elderly person. He is a statesman. He has got vast knowledge and political career. He was a leader of many political parties. In 1967 he formed one party which was called Janasangh. Again he formed another party called SVD. Then again he formed another party

called BKD. Then another party called BLD he formed. Now it is only LD. I do not know what the LD stands for. Is it for Lower Division? He is the leader of many political parties. He has vast experience. He said about the alliance of our DMK and the Congress Party. What we wanted was a stable government. Our former Prime Minister's only ambition—as he stated and which appeared in the papers—was that his life's ambition was to become the Prime Minister. That was achieved and he retired. I hope he may retire from politics for the welfare of the country. Many novel ideas were given during his regime like the rolling plan. The plan also rolled down; then came the tax on expenditure. The rolling Prime Minister, his counterpart of those days, Mr. Ramachandran also said that he wanted a rolling Prime Minister. I do not know whether they accepted it or not.

Sir, I would like to say this that while he was speaking, he said that he would never fail to support the good measures if implemented by this Government. But, at the same time, the very same day, when the Prevention of Blackmarketing and Maintenance of Supplies of Essential Commodities Bill was introduced here, this Bill was opposed by Lok Dal and other political parties. Actually this Ordinance was brought forth by Mr. Charan Singh. He was the father of that Bill. It was his own Bill. Now he opposes the very same Bill. The Bill was his child. Now he disowns his own child like the **Kaliyuga Vishwamitra**. He talked about the Sarkaria Commission also. How can both join together for the purpose of election? We put a question before the Prime Minister because it referred to my party, the D.M.K., to my leader Dr. Kalaignar Karunanidhi. I would like to say something about that also. In the very same House, only two parties persistently insisted upon the dismissal of the D.M.K. Government and the constitution of a Commission against our leader—one was the A.I.A.D.M.K. and the other was the C.P.I. in the House; the C.P.I. Leader, Shri M. Kalyanasundaram gave a memorandum to the President to dismiss this government. Now that party is with Mr Charan Singh. A Commission was constituted against Smt. Indira Gandhi as also against Shri Sanjay Gandhi and others like the Shah Commission, Gupta Commission, Reddy Commission and so on. The previous Government became the Commission Government. When I say it became the Commission Government, I did not mean that the Government got commissions from the blackmarketeers. Nothing of that sort. But, at the same time, they constituted Commissions after Commissions. When there was a split in the Janata Party, the very same Mr. Charan Singh sought the help of Mrs. Gandhi to form the Government. Is it fair? When he talked about the DMK and Indira Congress alliance in Tamil Nadu as an unholy alliance, can I ask their leader whether it is proper on his part to seek the help of Mrs. Gandhi to form the Government when he was asked to form it?

Then, Sir, he said that the prosecution which he launched against Mrs. Gandhi was according to law; I want to ask other members also as to why, when a matter was referred, they failed to prosecute my friend, Shri Fernandes as well as the Tamil Nadu Governor, Shri Prabhu Das Patwari, when both were involved in the dynamite case? At the same time, his son-in-law was not prosecuted when some members made charges against him. I want to ask the former Prime Minister, when he was talking of honesty and other things, when his own lieutenant, Shri Biju Patnaik, was put before the Commission, that is, H. R. Khanna Commission and Das Commission—both the Commissions by the Central Government—he is now Vice-President or a lieutenant of his own party and when one Shri A. T. Sarangi made charges against Mr. Biju Patnaik with a scandal of Rs. 15 crores—even though he

[Shri C. T. Dhandapani]

has admitted that it was against his own partyman, no action was taken against him?

Now I would like to say something about my own State. My own State's Chief Minister was protected by Shri Charan Singh. Shri Charan Singh always protected Shri M. G. Ramachandran. He collected money from many industrialists—once he collected money from the fleet owners to the tune of Rs. 75 lakhs for regularisation of the motor routes; the party also collected from the pawn brokers and from the sugar dealers to the tune of Rs. 25 lakhs. They also got commissions from the bootleggers and cinema theatre owners. Also they used to collect money from certain industries. And everything had been brought to the notice of then Home Minister, Mr. Charan Singh. The former Prime Minister, the then Home Minister, instead of taking action against the Chief Minister of Tamil Nadu. was good enough to accommodate two corrupt ministers in his own Cabinet. Now he is saying that 'I am a honest man; my Government was honest'. Everything is honest excepting himself!

Sir, one more thing that was brought to the notice of the former Prime Minister was the Bulgaria shipping deal. Rupees four crores was received an kick back by the Chief Minister of Tamil Nadu. All this was brought to the notice of the former Prime Minister, Shri Charan Singh, but no action was taken.

16.00 hrs.

AN HON'BLE MEMBER: MGR was agreeable for setting up a commission against himself.

SHRI C. T. DHANDAPANI: He had asked for a judge from the Supreme Court to head that commission. The Supreme Court said that they cannot spare a judge. MGR could have constituted his own commission. State Government can do it. He can go before the commission even now. He can ask the present Central Government for a commission but he would not do it as he knows the very next moment the commission will be constituted.

Sir, the law and order situation in Tamil Nadu is very bad. There is no law and order. Murders are taking place in various parts. Two years ago a lady named Prema was murdered in Basant Nagar. The case was not investigated and the culprit has not been brought to book so far. In Chetput the house of an old lady named Raja Lakshmi was looted and she was murdered in broad daylight. In this case also no arrests have so far been made. Recently about ten days ago another theft and murder took place in multi-storyed quarters of a government servants colony. The wife of a government employee was murdered. No action has been taken so far. Rapes have also taken place in Karaikudi, Coimbatore, etc. Rapes are taking place in many places. Instead of taking action against the culprits, Mr. M. G. Ramachandran is instigating all those culprits and anti-social elements.

Mr. Chairman, Sir, strikes have been banned. Our Communist friends are the supporters of Shri Ramachandran. Now no worker can go on strike for his just demands. Workers, weavers, cultivators, teachers, professors, students and engineers have been taken under custody when they put forward their just demands. Finally, police has also gone on strike. The pity is that police were allowed to form their association. They formed an association and elected their leaders and office bearers One day Shri Ramachandran called some of the police officials and asked them to form another association, viz., a minority association. A minority association was formed and the Chief Minister one day announced that he is going to recognise the minority association. The majority association consisting of 40,000 members went on strike with the result that they have

been arrested, beaten up and lathi-charged. More than one thousand police personnel have been dismissed. This is the position. The law and order situation in Tamil Nadu is nil.

Then, Sir, Shri M. G. Ramachandran, Janata Party, CPI and CPI(M) all joined together in Tamil Nadu and fought against DMK, Congress and Muslim League alliance. Mr. Ramachandran categorically announced in his election mainfesto which reads as follows:

> "The manifesto also expresses ADMK determination to work for the establishment of a national Government at the Centre to be truly representative of the States in the country.'

Then the report says:

> 'Both the Chief Minister Mr. M. G. Ramachandran and the State Finance Minister Mr. K. Manoharan, who released the mainfesto at a huge public meeting, explained that the Union Cabinet under the national Government should consist of representatives of the ruling parties in the States.
>
> They said that a one-party rule, one-leader rule and dynastic rule would spell danger to democracy and should not be accepted. This was the main issue in the current elections.

About Mrs. Gandhi's reported remark on regional parties, he said:

> 'This smacked of autocracy and dictatorship, and should be resisted'.

This is what he said in the conference. The leaders of other political parties were there, namely, Mr. P. Manickam (CPI), Mr. A. Balasubramaniam (CPI-M), Mr. P. Ramachandran, formerly Minister in the Janata Government, and so on. They were present at that meeting. In that meeting they continued to say that the ADMK pledged itself to fight Mrs. Gandhi's dictatorship from now on and after election.' Sir, this is an important thing. He has pledged so in front of all the leaders. I am telling to all our friends how he is pulling down your legs. That is why I am telling you all these things. He said:

> 'Fight Mrs. Indira Gandhi's dictatorship from now and after election'.

Now Mr. M.G.R. comes to Delhi and prostrates before Mrs. Indira Gandhi. So, this is the position, Sir.

We support Mrs. Indira Gandhi for this simple reason. Our leader Dr. Kalaignar Karunanidhi said this in a huge public meeting, in the beach meeting and Mrs. Indira Gandhi also addressed that meeting. This is what he said and quote him:

> 'We do not want a tamasha at Delhi. We want a Government—a good Government and a stable Government. We believe that only Mrs. Gandhi can give us a stable Government.'

This is what he stated, Sir. That is why we support this Government, a stable Government.

Before I conclude, Sir, I wish to refer to the call given to us on the 14th of January, 1980 by Mrs. Indira Gandhi. She said this and I quote:

> 'We have only one adversary—social and economic injustice. We have one goal to build a strong nation, self-confident, self-reliant, independent India. Come, now let us all work together.'

By saying this, Sir, I spport the Motion moved by Mr. S. M. Krishna.

श्री नगीना राय : (गोपालगंज) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव है मैं उसका समर्थन करता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इकोनामिक पौलिसी का बहुत स्पष्ट जिक्र किया गया है और यह भी कहा गया कि पुन: 20 सूत्री कार्यक्रम को लागू किया जायेगा जो

[श्री नगीना राय]

भी काम विकास के हुये थे उसे जनता पार्टी की सरकार ने विकास से संबंधित कार्य ढाई वर्ष में पीछे ढकेल दिया था उसे पुनः चालू किया जायेगा और किसानों को उचित मूल्य मिलेगा।

सबसे बड़ी बात यह है कि आज इस देश में किसान खुशहाल नहीं है। जो इस देश की हालत है उसमें आज भी सिचाई के पूरे साधन किसान को उपलब्ध नहीं हो पाये हैं। आज भी यहां की कृषि मौसम पर निर्भर करती है, और खास कर बिहार में उत्तरी बिहार बाढ़ का शिकार और दक्षिणी बिहार सूखे का शिकार होता है। नैपाल से जितनी नदियां निकलती हैं तमाम बिहार के उत्तरी हिस्से से हो कर आती हैं और किसानों की तमाम फसल को जो काट कर घर ले जाने के लिये होती है उसे बाढ़ से बहा कर साफ कर देती है।

आज हमारे देश में जो भी ऋण की व्यवस्था किसानों के लिये की गई है वह इतनी मंहगी पड़ती है कि जिसका ठिकाना नहीं। आज हिन्दुस्तान के रिजर्व बैंक से जो पैसा ऋण के रूप में दिया जाता है उस पर 15 फीसदी सूद पड़ जाता है। यदि हम दुनिया के अन्य देशों को देखें, तो थाईलैंड का रिजर्व बैंक 1 परसेंट सूद लेकर को-आपरेटिव बैंक को पैसा देता है, जो कि किसानों तक पहुंच कर 4 परसेंट पड़ता है। लेकिन हिन्दुस्तान का रिजर्व बैंक जो पैसा देता है, उसका सूद किसानों पर 15 परसेंट पड़ता है। आज हिन्दुस्तान के खेतिहरों की हालत बहुत खराब है। वास्तव में दुनिया भर में खेतिहर तबाह हैं और खेती के काम को छोड़ना चाहते हैं। अमरीका में 1890 में 93 परसेंट लोग खेती करते थे, जबकि आज सिर्फ 7 परसेंट लोग खेती के काम में लगे हुये हैं। जापान में सिर्फ 8 परसेंट लोग खेती करते हैं, मगर वे दूसरी इंडस्ट्रीज में भी लगे हुए हैं। अगर हिन्दुस्तान के गृहस्थ को उचित मूल्य नहीं मिलेगा, तो वह खुशहाल नहीं हो सकेगा और हमारी इकानोमी बिगड़ती चली जायेगी। यह खुशी की बात है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में कहा गया है कि किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जायेगा।

जो चुनाव हुए, उनके परिणाम देश के सामने हैं। जनता पुनः श्रीमती गांधी को पावर में लाई है। हमारे विरोधी दल के मित्र बड़ी लम्बी चौड़ी बातें करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि मुजफ्फरपुर में श्री जार्ज फर्नान्डीज चुनाव लड़ रहे थे। वह कोई बहुत बड़े कैपिटलिस्ट नहीं हैं, कोई पूंजी का भंडार उनके पास नहीं है, लेकिन करोड़ों रुपये उन्होंने वहां बहाये। किस नीति से बहाये? वहां लोगों में 500 साइकलें बांटी गईं, घड़ियां बांटी गईं। बूथ-कैपचरिंग के लिये पांच-पांच हजार रुपये का ठेका दिया गया। तीन-तीन हजार रुपये पहले दिये गये और बूथ कैपचर करने के बाद बाकी दो-दो हजार रुपये दिये गये। इसके अलावा उन्होंने कास्ट रायट्स कराने की कोशिश की। श्री जार्ज फर्नान्डीज ने पैसे का जाल बिछा दिया, करोड़ों रुपया खर्च किया। वह अपने आपको सोशलिस्ट कहते हैं। क्या वह पूंजीपतियों के एजेंन्ट हैं, क्या उनके कल-कारखाने हैं? उनके पास पैसा कहां से आया?

बंगाल में क्या हुआ है? वहां वोटरों को टेररा़इज किया गया, गरीब वोटरों को वोट देने से रोका गया। अगर आज वहां पर एसेम्बली के इलैक्शनन्ज हों, तो बंगाल के लोग सत्तारूढ़ पार्टी को बाहर धकेल देंगे। आज बंगाल में कोई ला एण्ड आर्डर नहीं है। इस देश में एक द्रोपदी के चीर-हरण पर महाभारत हुआ था। लेकिन आज बंगाल में शील-हरण की घटनायें रोज घट रही हैं और सरकार सो रही है। आज बंगाल की हालत दयनीय है।

आज देश में अराजकता फैली हुई है, मगर यह खुशकिस्मती की बात है कि जनता ने यह विश्वास प्रकट किया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी देश में फिर शांति और व्यवस्था कायम कर सकेंगी। आवश्यकता इस बात की है कि ला एण्ड आर्डर की पोजीशन को तुरन्त सम्भाला जाये।

जिन राज्यों की सरकारें नाकाबिल और निकम्मी साबित हो रही हैं, जहां की जनता ने कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत से जिताया है उन्हे तुरन्त बर्खास्त करना चाहिये और वहां पर ला एण्ड आर्डर रेस्टोर करना चाहिये। आज उन सरकारों के बने रहने का क्या औचित्य है? इसी आधार पर इन लोगों ने 1977 में राज्य सरकारों को तोड़ दिया था। लेकिन आज चौधरी साहब को यह बात खटकती है, इससे उनको बेचैनी हो रही है। लेकिन उनकी सरकार तो वैसे ही टूट रही है और उनकी पार्टी समाप्त हो रही है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह स्पष्ट निर्देश होना चाहिये था कि जनता द्वारा दिये गये मैंडेट के आधार पर उन सरकारों को तुरन्त बर्खास्त किया जाएगा और उन राज्यों में नये चुनाव कराये जायेंगे।

मैं बहुत ठंडे शब्दों में कहना चाहता हूं कि ये राज्य चलाने के नाकाबिल हैं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। मुसलमान भाइयों के मजार होते हैं। सूट बूट लगाकर बड़े बड़े ब्लैक मार्केटियर, स्मगलर, दुकानदार और रहनुमा लोग मजार के पास पहुंचे और जो वहां पर खड़े हुये उनकी गाड़ियां सड़क पर खड़ी थीं। जो किसान खेत जोतते थे, कोड़ते थे, सोहते थे और हल चलाते थे, उन्होंने देखा कि यहां भी तस्वीर ही बदल गई है ये लोग मजार पर आ गए हैं।

उन लोगों की आशा जागी । वे लोग इकट्ठे हो कर मजार पर गए और यह पूछा कि ये लोग क्या करने आये थे ।

क्या कहा , क्या किए ? तो रुह ने कहा–

आये थे मेरी कब्र पर, सिगरेट धराकर
चल दिए ।

दिए में जो तेल था, सर पर लगा कर
चल दिए ।

इतना ही कह कर मैं समाप्त करता हुं ।

श्री कृष्ण दत्त (शिमला) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति जी ने संसद् के दोनों सदनों के समक्ष जो भाषण दिया उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । जहां तक हमारे देश की स्थिति का ताल्लुक है उसका इसमें जिक्र किया गया । देश के अन्दर पीछे जो आपस में साम्प्रदायिक हमले हुए देश का मान कटा और देश के अन्दर जो एनार्की फैली, हमारी सरकार पूरी तरह उस से खबरदार है । पिछली सरकार ऐसी सरकार थी जो ला एण्ड आर्डर मुल्क के अन्दर कायम नहीं रख सकी । हिन्दुस्तान के लोगों ने देखा कि वह सरकार जब बनी तो महात्मा गांधी की समाधि पर उन्होंने कसम खाई कि हम आपस में नहीं लड़ेंगे लेकिन अपनी उस लड़ाई के नतीजे में सारा देश उन्होंने बरबाद कर दिया । यह एक बहुत बड़ा उदाहरण उन्होंने हमारे सामने पेश किया ।

मैं अपने क्षेत्र हिमाचल प्रदेश की बात कहना चाहता हूं । जिस प्रकार से वहां नेकरधारियों की सरकार बनी, उसके बाद उन्होंने वहां रिज पर कसम खाई कि बापू , हम बड़ी कोठियों में नहीं रहेंगे , साधारण बंगलों में रहेंगे, गरीबों की सेवा करेंगे लेकिन उन्होंने क्या किया ? जो यहां केन्द्र में उनके स्वास्थ्य मंत्री थे राजनारायण जी, वह वहां पर पहुंचे । वह इत्र साथ रखते थे, उन्होंने इत्र उनकी तरफ फैंका और कह दिया कि आपकी शुद्धि मैं कर रहा हूं । उसके बाद दो मिनट के अन्दर उनको मंत्री पद से निकाल दिया गया । वह सरकार जो भी जो कहती थी कि हम महात्मा गांधी के पुजारी हैं , उसने यहां इस देश में ही नहीं , बाहर भी हमारे मान को घटाया । हमारे भाइयों ने जो यह कहा है कि पिछली जो इंदिरा गांधी की सरकार थी वह तानाशाह थी , तो तानाशाह तो आप थे जिन्होंने जब चिकमंगलूर से हमारी नेता चुन कर आयीं तो अपनी मेजारिटी के बलबूते पर उन को निकाल दिया । तो तानाशाह तो आप हैं न कि हम तानाशाह हैं । हमने चुनाव कराया है, इस देश की आर्थिक स्थिति को हमने मजबूत किया है हमारे समय में देश के अन्दर परमाणु विस्फोट हुआ , हमारे देश के लोगों ने बंगला देश के लोगों का यहां पालन पोषण किया । लेकिन वह सरकार तो अपने घर के लोगों का पालन-पोषण करने में लगी रही । जो भी उन्होंने किया अपने आदमियों का किया चाहे वह पूंजीपति थे चाहे कुछ भी थे उन्हीं की इन लोगों की मदद की । जहां तक अपोजिशन के दूसरे लोगों का ताल्लुक है अगर वे देश के हित की बात करते हैं तो हमारा कोआपरेशन बराबर अपोजिशन के साथ रहता है । मगर वे इस तरह की बातें करते रहे कि दस साल के अन्दर देश की गरीबी को हटा देंगे, गरीबी को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे इस तरह का आश्वासन नौजवानों को दिया और यहां पर सर्विसिज के लोगों को यह कह दिया कि यह तो कांग्रेस वालों के टाइम के भरती किए हुए हैं इनके ऊपर हमारा एतबार नहीं है इनके केन्द्र के मंत्री इस तरह की बातें कहते रहे हैं, इसका परिणाम क्या निकला ? इस देश के नौजवानों ने देख लिया कि उनको बहुत झूठ तरीके से फुसलाया गया । आज ये फुसलाये नहीं जा सकते । आज सारे लोग जाग्रत हैं और वे यह समझते हैं कि हमने स्थायी सरकार देश को दी है उसी से हमारा भला होगा । आप कहते हैं कि हमें तो कम वोट मिले हैं लेकिन आपने जो चार पांच पार्टियों का टोला बनाया, उसके बाद भी आप इतने मत प्राप्त नहीं कर पाये कि अपनी सरकार कायम रखते । देश की जनता ने जहां आपको बहुमत दिया था वहां आप अपने आप ही खत्म हो गए, अपनी खुदकशी कर ली ।

जहां तक हिमाचल प्रदेश का ताल्लुक है, वहां जो सरकार बनी, उस सरकार ने बहुत बड़ी धांधली मचाई हुई है । वहां पर वाइस-चांसलर इस तरह के लोग रख दिए गए जो निकरधारी थे । उन्होंने बच्चों के ऊपर गोलियां चलवाईं, लाठियां चलवाईं, ला एण्ड आर्डर को खराब कर दिया । आज डीजल की बात आती है —हिमाचल प्रदेश में जो आलू या सेब की फसल पैदा होती है उसको उन्होंने बिलकुल बरबाद कर दिया । हिमाचल प्रदेश में क्या हो रहा है ? वहां जनता पार्टी के विधायक आलू के सवाल पर विधान सभा के बाहर हड़ताल पर बैठते हैं । जिस दल के विधायक हड़ताल पर बैठे और जहां की सरकार 50 रुपया बोरी का भाव मुकर्रिर करे—यह सब क्या हो रहा है ? वहां की सरकार बिलकुल कानून-शिकनी कर रही है उस सरकार को फौरन डिस्मिस किया जाय, हटा दिया जाय ताकि वहां के लोग सुख की सांस ले सकें ।

हमारे यहां डीजल की कमी है । इसका क्या कारण है ? इन्होंने ऐसे लोगों को पैट्रोल के पंप दिए हैं जो निकरधारी हैं । इन्होंने जनता का भला करने के बारे में नहीं सोचा सिर्फ अपने लोगों को ही फायदा पहुंचाने की कोशिश की है ।

[श्री कृष्ण दत्त]

हमारे राष्ट्रपतिजी ने अपने एड्रेस में 20 सूत्री प्रोग्राम का जिक्र क्या है यह बहुत अच्छा प्रोग्राम है इस में फैमिली प्लानिंग का जिक्र किया गया है । मैं आपको बतलाऊ ---जहां जहां जनता पार्टी की सरकारें हैं जब हम आज इलैक्शन जीत कर आए तो उन्होंने अपने आर० एस० एस० के वर्करों के जरिए जनता में यह प्रचार करना शुरु कर दिया कि अब इंदिरा गांधी की सरकार आ गई हैं फैमिली प्लानिंग करायेगी । इस तरह की गुमराह करने वाली बातें जनता में फैलायी जा रही हैं, हमें इन सब बातों से सतर्क रहना चाहिए । मैं कहना चाहता हूं--जहां आप लोगों ने गलती की है और जहां अपोजीशन वालों ने गलती की है हमें उन सब से सबक लेना चाहिए । और कंस्ट्रक्टिव काम की तरफ आयें जिस से लोगों को सुख मिले ।

यहां पर मजदूरों के कल्याण की बातें कहीं जाती हैं लेकिन ये इस बात को नहीं देखते कि अपने टाइम में बेरोजगारी बढ़ाते गए हैं. ला एण्ड आर्डर खराब करते गए हैं । अपने टाइम में जयप्रकाश जी के बारे में जिन का ये लोग लोक नायक के रुप में नाम लेते हैं इन्हीं लोगों ने इसी माननीय सदन में उन को मृत घोषित करके प्रस्ताव पास किया था । इन के रेडियों को भी उसका पता न था । मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने इस मुल्क के अन्दर कोई अच्छा काम नहीं किया । लेकिन जहां तक हमारी सरकार के कामों का तांल्लुक है--हमारी सरकार की कुछ नीतियां हैं कुछ पालिसीज हैं । इंदिरा जी की इन नीतियों के साथ हम सब का पूरी तरह से जोरदार समर्थन है और देश ने भी उन नीतियों के आधार पर इंदिरा जी को पूरा समर्थन दिया है संजय गांधी को समर्थन दिया है जो लाखों वोटों से जीत कर आये हैं । आप कहते है कि ये तानाशाह है । ये तानाशाह नहीं हैं अगर ये तानाशाह होते तो देश के अन्दर चुनाव न होते । आप लोगों ने देश का बेड़ा गरक कर दिया है इतना नुकसान किया है इतनी तबाही की है जिसका कोई हिसाब नहीं है । लेकिन हमारे लोगों में एक से एक आला दर्जे के लोग हैं आल दर्जे के मंत्री हैं मैम्बर पालियामैन्ट हैं जिन को जनता ने चुन कर भेजा है और बहुत ज्यादा वोटों से चुन कर भेजा है । आप लोगों ने हर तरह से हमारे रास्तों में रुकावटें डाली लेकिन हमारे वोटरों ने कुरबानी देकर हमें इस संसद में चुनकर भेजा है ।

मैं आपका बड़ा आभारी हूं आपने मुझे बोलने का मौका दिया । हमारे राष्ट्रपति जी ने एक बहुत अच्छा भाषण दिया है जिस का हम पुरजोर समर्थन करते हैं । धन्यवाद ।

DR. KARAN SINGH (Udhampur): Mr. Chairman, Sir: As we enter the new decade, the nation faces a grave and multi-dimensional crisis, overcoming which will require the mobilization of all the material, moral and spiritual resources of the nation. The dimensions of this crisis are many. But broadly, they fall into 3 categories—the economic, political and international.

In any nation where millions still live below what is generally accepted as the human standard of living, economic problems must necessarily get priority; and I am glad that the President's Address has highlighted the importance of getting the economy moving again. Apart from our long-standing poverty, two factors have increased the burden upon our people. The first is this unprecented drought, the worst in living memory which has covered vast areas of this nation, and has placed an almost unbearable burden upon the already economically weak sections of our society. And secondly, this constant increase in oil prices that takes place, adding hundreds of crores of rupees to our bill every year, is something. beyond our control, which continues to put a great burden upon our resources.

Therefore, as a top priority, we must revitalise the economy, increase production and productivity and instil a work ethic, a philosophy of work into our management as well as the labour. I welcome the emphasis on the minimum needs programme which has been mentioned, because unless we are able to give our people the five needs of life; food, shelter, clothing, health and education and one more need which has not been mentioned in the President's Address and that is employment even if you give the needs of life, and you are not able to give employment, you will find widespread frustration that is growing among the younger genations. I am surprised that the President's Address has not made any mention of this problem of unemployment and the frustration that the younger generations in this country are feeling as a result of lack of em-

ployment opportunities. This is important. Along with the minimum needs of life. This need of employment must be added as an essential pre-requisite.

Energy has been mentioned. What is required is not only a comprehensive energy policy but an agency which would coordinate the various activities in the energy field, whether they relate to petroleum products or to thermal power, hydro-electric power or nuclear energy, solar energy or any other type of energy that we may develop in this country. Unless there is a comprehensive agency which will tie together these various things, we will find ourself in great difficulties in the years and decades ahead. Therefore, I express the hope that a comprehensive agency of this nature will be developed very soon.

The President has mentioned the question of environment. I am glad he has done so, because we must not make the mistakes that the western nations have been making, where their affluent societies are rapidly becoming affluent societies. The pollution is becoming so widespread that they are virtually unable to breathe the air. In Tokyo, people go round in gas masks, the position is so bad. Therefore, now that we have this opportunity to learn from the experience of the West, we have got to take care that our economic development does not pollute the environment and that is where the National Committee for Environmental Planning and Coordination needs to be revitalised. There was a Elect Committee on the Prevention and Control of Air Pollution of which I had the privilege to be Chairman. We travelled throughout the country; and on the last day of the Sixth Lok Sabha, on the 18th May, we presented our Report to Parliament. In that Report, we have made recommendations not only with regard to the Air Pollution Bill but also some general recommendations including steps to save the Taj Mahal from pollution and disintegration. We have made certain concrete proposals with regard to the Mathura Refinery, with regard to other steps that need to be taken. I hope that the Government will lose no time in bringing before this House that Prevention and Control of Air Pollution Bill early in the next session. These are some of the points with regard to the economic policy that I think needs special attention.

Turning to the political scene, there is now, hopefully stability at the Centre. But in the system of our Constitution, stability at the Centre by itself is not enough. Our Constitution envisages a federal polity where the Centre and the States are to be in relationship with each other; and I think it is very important that we should not make mistakes that the Janata Party had made in 1977, which we, on this side of the House, very strongly opposed even then when they dissolved nine State Assemblies on the plea that the result of the general elections had shown that the people thought differently. Let us be clear, in our country people vote differently for the Parliament, very often they vote differently for the State Assemblies, because the problems facing the people are different. The issues before the people are different. Therefore, to argue that because a certain political party has come to power in the Centre it has the mandate to sweep aside all the State Assemblies is a very dangerous and pernicious theory. I express the hope that with their new majority, the Ruling Party will not fall into the same mistake that was made in 1977, because that cuts at the very root of the federal polity that the constitution-makers had envisaged.

The second point that I should like to make on the political scene is with regard to North-east. North-east India is in turmoil. 12 Members of Parliament are missing because they have not been elected and the whole North-east India, particularly Assam, is in a way in revolt. The Prime Minister had said that we require a national approach, not a partisan ap-

[Dr. Karan Singh]

proach. That is correct. I have two concrete suggestions to make. The first is that the Prime Minister herself, soon after this session of Parliament, should make a visit to Assam, because personal emissaries howsoever distinguished they may be are never really able to get a full grasp of the situation. I think the Prime Minister's presence there is important.

Secondly, it is the question of foreigners which is, as I see it, the crux around which the controversy rages. There is a plethora of pacts that have taken place over the last thirty years starting with the Nehru-Liaquat Ali Pact, the Indira-Mujib pact and the Morarji-Zia understanding. Then there are a number of constitutional provisions, there are the Foreigners' Act and the Citizenship Act of 1955. I should suggest for the consideration of the government that a high-powered commission under the chairmanship of a retired Chief Justice of India should be set up without delay to look into the whole matter in an objective manner and come to some finding with regard to the question of foreigners.

AN HON. MEMBER: Shah Commission?

DR. KARAN SINGH: You can have Shah if you like, if you want him to take up this matter. Unless this is looked into in a dispassionate manner, you will never come to a firm conclusion. This is the strategy we have adopted. In our own state of Jammu and Kashmir. There are certain very vexed problems; there has been the problem of regional imbalances in Jammu, Kashmir and Ladakh. A commission has been set up under a retired Chief Justice, Mr. Sikri and it is trying to tackle the problem. I am appearing before that commission shortly. It is trying to take a dispassionate view and come to some abiding solution for this problem. When passions are aroused, particularly in this sort of situation, it is necessary that the matter should be looked at with a certain amount of detachment. I do not think that people who are actually involved in this situation can bring that degree of detachment to bear upon the problems. It is a concrete suggestion that I should like to make because I feel that the Assam situation is not a party problem. It is a national problem. All of us are deeply concerned about it. Coming as I do from a State where many of these problems had been before us for over thirty years—including very strong secessionist tendencies—I am perhaps more acutely aware than most others, of the complexities and the nuances that we face in the border areas and therefore this must be approached with sympathy and understanding through the mechanism I have suggested.

With regard to the international situation, I have one difference with the Prime Minister. She has stated that the centre of the cold war is now near our borders. I think that the centre of the hot war is now near our borders because we have a situation where the two super powers and China are likely to come into frontal confrontation right on our borders and that I think represents a grave threat to the security of our nation. There will be a debate on Afghanistan; the Speaker has promised it and the Prime Minister has agreed to it, and therefore I will not go into those details except to say that this is a national problem and we who are living in Jammu & Kashmir are particularly sensitive to this because we have been the victims four times. In 1947 there was the first Pakistani attack when lakhs of people in Jammu & Kashmir were uprooted; 30,000 square miles of our territory is still in Pakistani occupation. In 1962 when there was a war again, our people were uprooted and made refugees. In 1965 when the Chinese attacked, we find that 10,000 square miles of Indian territory in the State of Jammu & Kashmir are still under their occu-

pation. Even in 1971, when we won the great and famous victory which will go down in history as one of our most glorious hours, 25,000 people from Jammu in the Chamb area were rendered homeless. Some refugees are still wandering around without being properly settled. We have borne the brunt of these problems in the last thirty years. Therefore, whereas the whole nation is naturally involved in this, we are very close to the mouth of the volcano.

Therefore, I would like to say that we have got to take every step necessary to safeguard our security, to see that destabilisation of this region does not proceed any further and to try and see that some initiative is taken by India in this matter. It is not enough for us to tag along with other countries. We are the major power in this region. Our national interests are vitally affected and, therefore, we would expect from the Government and the Prime Minister some new initiative. I am glad that President Valery Giscard d'Estaing and the Prime Minister made a statement in this regard. What is important is that it must not be a partisan policy. It must be a national policy.

This brings me to the importance ultimately of involving the Opposition in the solution of these varied problems, the crises I have mentioned. In order to successfully overcome them, two things are required. One is effective Government. By effective Government I do not mean authoritarian Government or heavy headed Government or have handed Government, but Government that genuinely tries to understand and tackle the problems of the people; a Government that is committed to restructuring the national polity and economy; that sore of Government which produces results and solutions. Massive mandates have been produced in the past. In 1971 there was a massive mandate. In 1977 there was a massive mandate. But what happened? Ultimately, we frittered away those advantages, we did not take advantage of those situations to really solve the problems of the people. The people of India are long suffering. They are very patient. But they have proved that they are not to be taken for granted. They can throw out Governments and they can throw in Governments, and the Governments once thrown in can equally be thrown out again. Therefore, I would say that this Government despite its majority, is a Government that is on trial. The people will be watching carefully as to what it is that is actually done to help solve their problems and, therefore, as I said the first requisite is an effective Government. The second requisite is ..... (*Interruptions*)

SHRI N. G. RANGA (Guntur): We have an effective Government.

DR. KARAN SINGH: We do not know. Yet it is too early to say, Prof. Ranga. It is too early to say. It is only 15 days old.

The second pre-requisite is the role of the Opposition. The role of the Opposition is co-equal in importance with that of the Government. It is true, we talk of the massive mandate and it is a remarkable achievement. I agree Smt. Indira Gandhi single handedly toured this whole nation from Udampur in the North down to Kanya Kumari in the South, and a lot of people were elected. However, I hope I will not be called unshivalrous if I point out, with that of the massive mandate the Government represents 43 per cent of the electorate. And 57 per cent ....

SHRI N. G. RANGA: It is an old story.

DR. KARAN SINGH: It is not an old story. It is like you, it is an ever young story. That is a fact.

THE MINISTER OF WORKS AND HOUSING AND PETROLEUM AND CHEMICALS (SHRI P. C. SETHI): The other 57 per cent is divided. It is not one.

DR. KARAN SINGH: May I complete the point?. I am saying that two things are required to solve the problem. The first thing is an effective Government. The second thing is an Opposition that is vigilant, an Opposition that fulfils its responsibility. We may be small in numbers but we do represent, divided though we are, 57 per cent of the people of India who voted. Therefore, we have a responsibility. This responsibility, I can assure you on behalf of those sitting on this side of the House, is to support the Government where the national interest requires and to oppose the Government where the public interest demands. This is going to be our duty. I can assure you that this we will do without fear or favour. We will fulfil our responsibility so that the new India of which Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru dreamt could come into being and the peril that faces us in this very dangerous decade can be overcome. We on this side of the House will be vigilant because constant vigilance is the only way in which the Government can be forced to function in a responsible manner. We will fulfil our responsibility in the hope that the rules of the game will be accepted and we will together move forward towards building that India for which all of us and the ones who came before us have been labouring for many years.

श्री शिवराज वी० पाटिल : (लातुर) : श्रीमन्, लोक सभा चुनाव के बाद जो राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हुआ है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस अभिभाषण को पढ़ने के बाद हमको ऐसा लगता है कि कांग्रेस पक्ष ने इतनी बड़ी मैजारिटी में चुन कर आने के बाद खुशी मनाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी क्या है यह समझने की कोशिश की है। हमारे देश के सामने प्रश्न क्या है यह ढूंढ कर निकालने की कोशिश की है और वे प्रश्न किस प्रकार से हल किए जा सकते हैं यह बताने की इसमें कोशिश की गई है। और मैं समझता हूं कि जब कि लोगों ने इतने बड़े पैमाने पर कांग्रेस पक्ष के उम्मीदवारों को यहां भेजा है तो यह कहना गलत होगा कि 42 प्रतिशत लोगों का ही हम प्रतिनिधित्व करते हैं और बाकी लोगों का प्रतिनिधित्व जो लोग विरोधी बैंचों पर बठ हुए हैं वे करत हैं, यह कहना गलत होगा।

डा० कर्ण सिंह : यह तथ्य है।

श्री शिवराज वी० पाटिल : यहां पर जो चुन कर नहीं आये हैं उनके भी मतों का ख्याल किया जाना चाहिए। मैं इन बातों के लिए कुछ नहीं कहना चाहता। मगर मैं यह कहना चाहूंगा कि लेजिस्लेटिव मेसर्ज के सम्बन्ध में राष्ट्रपति जी ने जो अपने अभिभाषण में कहा था वह कदम पहले हमने यहां आ कर उठाया। घटना दुरुस्ती के सम्बन्ध में जो उन्होंने बताया, इसके परिच्छेद 32 में बताया गया है कि हम संविधान को दुरुस्त करेंगे और जो शेडयूल्ड कास्ट्स और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के भाई हैं उनको लेजिस्लेचर में बैठने के लिए और 10 साल का मौका देंगे। वह पहला कदम अभिभाषण होते ही दो-तीन दिन के भीतर ही उठाया गया है, और यह खुशी की बात है कि इस सदन के सारे सदस्यों ने उस संविधान की दुरुस्ती का समर्थन किया है। यह हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है।

यहां पर कुछ माननीय सदस्यों ने अपने भाषण में कहा कि इसमें नई चीज कौन सी है ? यह तो सारी पुरानी चीजें हैं। मैं यह मानता हूं कि इसमें बहुत सारी नई चीजें नहीं हैं। मगर जो दो, तीन साल बीते हैं उसमें जो चीजें हो रही थीं, उससे अलग और नई चीजें जरूर इसके अन्दर हैं। यह हो सकता है कि इसके पहले जो 28, 30 साल में हो रहा था उससे नई चीजें नहीं हैं, मगर जो दो-तीन साल में हो रहा था उससे अलग चीजें इसमें जरूर हैं।

मैं सदन का ध्यान अभिभाषण के परिच्छेद 9 की ओर खींचना चाहता हूं। क्या कहा गया है उसमें। उसमें कहा गया है कि हम नियोजन की पद्धति से अपनी अर्थ व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं। मैं पूछना चाहूंगा कि यहां गये तीन साल में क्या इस सदन में बैठकर जो नियोजन की कल्पना थी उसको तोड़-मरोड़ कर हमारे देश के सामने रखा गया था कि नहीं ? इस सदन के सारे सदस्यों को याद है कि इस देश में नियोजन की कल्पना पंडित जवाहर लाल नेहरू सबसे पहले लाये, और उस समय भी उसका विरोध किया गया था। लोगों ने कहा था कि यह कल्पना है, प्रदेश की कल्पना है और यह यहां पर नहीं चल सकेगी, यह कल्पना काम नहीं कर सकेगी ? परन्तु पंडित जवाहर लाल नेहरू का वह नेतृत्व था, उनका जो व्यक्तित्व था उसके आधार पर वह कल्पना यहां आयी और देश में चलती रही। परन्तु ज्यों ही पंडित जवाहर लाल नेहरू हमारे बीच से चले गय, हम सब को याद होगा, इस नियोजन की कल्पना को छुट्टी दे दी एक साल की। नियोजन की कल्पना छोड़ दी गई और प्लान हालिडे की कल्पना आई। उसके बाद श्रीमती गांधी के आने पर नियोजन की कल्पना फिर आई। ज्यों ही इन्दिरा जी के हाथ से राज्य की बागडोर चली गई, तो फिर नियोजन की कल्पना को तोड़-मरोड़ कर जनता के सामने रखा गया। कहा गया कि अब हम रोलिंग प्लान रखना चाहते हैं। रोलिंग प्लान

क्या है, यह हमारी समझ में नहीं आता है। रोलिंग प्लान और बजट में कितना अन्तर है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। हम समाज को बदलना चाहते थे, उसकी आर्थिक व्यवस्था को बदलना चाहते थे, और नियोजन की पद्धति से बदलना चाहते थे, मगर नियोजन को छोड़ दिया गया। मैं बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि अगर नये शासन के आने के बाद कोई नई चीज आई है, तो वह यह है कि नियोजन की कल्पना एक नया रूप धारण कर के आई है और हम उसके द्वारा समाज और उसकी आर्थिक व्यवस्था को बदलना चाहते हैं।

यह बड़े आनन्द की बात है कि अभिभाषण के परिच्छेद 17 में साइंस और टैकनालोजी का उल्लेख किया गया है। हम जानते हैं कि संसार की जो प्रगति हुई है, वह विज्ञान और टेकनालोजी के द्वारा हुई है। हम संसार का 1700, 1800 वर्ष का इतिहास जानते हैं कि जब आदमी अपने हाथ-पैर से काम करता था, तो उसकी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। लेकिन जब उसके हाथ में विज्ञान और टेकनालोजी की शक्ति आई तो उसकी प्रगति होने लगी।

इस जानकारी के आधार पर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने हमारे देश में रिसर्च या अनुसंधान का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया। रिसर्च पर बहुत पैसा खर्च होता है और कभी-कभी कहा जाता है कि यह फिजूल खर्च है क्योंकि इससे हमारे हाथ में कुछ नहीं आता है। लेकिन रिसर्च कोई ऐसी मशीन नहीं है कि उसमें कोई सामान डालने से कोई तैयार माल हमारे हाथ में आ जाये। रिसर्च तो हमेशा जारी रहती है और कभी एक ऐसा समय आता है कि कोई इनवेन्शन या डिसकवरी हमारे सामने आती है, जिसकी सहायता से हम पूरे समाज के स्वरूप को, उसके आर्थिक स्वरूप को बदल सकते हैं। साइंस और टेकनालोजी को इस दृष्टि से देखना जरूरी है।

लेकिन जब जनता पार्टी का शासन आया—जनता पार्टी के विरोध में बोलने में मुझे कोई खुशी नहीं है, लेकिन जो कुछ हुआ है, वह संसद और देश के सामने आना चाहिए—तो हमने आगे देखना छोड़ दिया और पीछे देखना शुरू किया, हम ने भविष्य की ओर देखना छोड़ दिया और भूतकाल की ओर देखना शुरू किया। हमने विज्ञान की ओर देखना छोड़ दिया और आदमी के हाथ-पैर की ओर देखना शुरू किया। आदमी के हाथ-पैर और शरीर की ओर देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन विज्ञान की जो महान् शक्ति है, संसार में एक जर्रे-जर्रे में जो शक्ति है, उस पर अधिकार कर के हाथ-पैर, शरीर और मस्तिष्क की मदद करना बहुत आवश्यक है।

लेकिन साइंस और टैकनालोजी की ओर देखने का दृष्टिकोण बदल गया, गलत हो गया। लेकिन उसका परिणाम आज हमको देखने को नहीं मिलता है। अगर साइंस और टेकनालोजी के प्रति हमारे दृष्टिकोण में कोई गलती होती है, तो आज हम नहीं कह सकते कि उससे क्या बुराई या कमी हुई है। दस साल के बाद हम को उसके फल भुगतने पड़ेंगे, दस साल के बाद हम महसूस करेंगे कि अगर हम इस मार्ग पर चले होते तो अमुक चीज हमारे हाथ में आ जाती और उसके द्वारा हम अपने देश की प्रगति कर सकते थे। यह खुशी की बात है कि पिछले ढाई-तीन साल का दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और नया दृष्टिकोण अपनाया गया है।

हम कहते हैं कि गरीबी हटानी है, बेकारी खत्म करनी है, देश को समृद्ध बनाना है, शक्तिशाली बनाना है। लेकिन केवल नारों से यह काम नहीं होने वाला है। नियोजन के द्वारा समाज का स्वरूप बदलने से, विश्व में जो शक्ति है, उसको अपने हाथ में ले कर उसका उपयोग करने से ही हम यह काम कर सकते हैं। अगर हम ने इस दिशा में कदम नहीं उठाया, प्रयास नहीं किया तो ये सब काम नहीं हो सकते हैं। यही दृष्टिकोण आज नई सरकार का है और इसी दृष्टि से यहां पर काम किया जा रहा है।

तीसरा प्वाइंट मैं परदेश नीति के संबंध में रखना चाहता हूं। परदेश नीति के संबंध में सम्माननीय सदस्य बाबू जगजीवन राम ने यह दुरुस्त कहा कि हमें बड़े एहतियात से काम लेना जरूरी है। एक-एक लफ्ज हमें सोच-समझकर बोलना है। चीजें इतने नजदीक, हमारी बाउंड्री के पास आ गई कि अगर हम कुछ गलत कदम उठाएं या गलत बोलें तो इस का असर हमारे उपर हो सकता है। यह समझ कर हमें बोलना होगा और यह समझ कर हमें काम करना होगा। मगर क्या करना है, क्या बोलना है, यह तय करते समय एक इतिहास है हमारे देश का, उस को भी याद रखना जरूरी है। 1962 की घटना हम याद करें 1962 की घटना कैसे हुई थी? उस समय इस देश के अंदर और इस के बाहर कुछ लोगों के ऐसे भाषण हुए थे जिस की वजह से कहा जा सकता है कि कुछ ऐसी चीजें हुईं जिस के कारण हमें कुछ दिन के लिए तकलीफ उठानी पड़ी। कुछ दिन के लिए कुछ नादुरुस्ती यहां पर हो गई। आज भी हमें याद रखना पड़ेगा कि यह किसी एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, किसी एक सरकार का प्रश्न नहीं है, यह सारी पार्टीज का, सारे समाज का और सारे देश का प्रश्न है और इस संबंध में हम जो कुछ भी बोलना चाहें, बहुत ही सोच-समझ कर हमें बोलना होगा। शीतयुद्ध या कोल्ड वार और हाट वार, यह भी ऐसा लग रहा है कि हमारी बाउंड्री के नजदीक आ गया है और अगर हमें उस में पैट्रोल नहीं डालना है, तेल नहीं डालना है तो यह सोच-समझ कर हमें बोलना होगा कि कहां तक हमें जाना होगा और कहां पर रूकना होगा।

हमारे इस देश की परदेश नीति क्या हो सकती है। यह तय करते समय सब से पहले

[श्री शिवराज वी० पाटिल]

हमारा काम यह देखना होगा कि हम जो अपने इंटरेस्ट हैं उन को कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और हम अपने देश का संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं । यह हमें ध्यान में रखना होगा । इसके बाद इस संसार के अंदर शांति कैसे स्थापित होगी यह हमें देखना होगा । इस के बाद हमें देखना पड़गा कि जो तत्व हम आगे रखते है, उन तत्वों को हम छोड़ न दें । मगर जब हम उन तत्वों को इस्तेमाल में लाएं तो उस समय कोई ऐसी भाषा न निकालें कोई ऐसा वाक्य अपने वक्तव्य में न निकालें जिस की वजह से हम ऐसी कुछ परिस्थिति संसार के अंदर पैदा कर दें कि हमारे दोस्त, दोस्त न रहें और जो दोस्त नहीं है वह भी दोस्त न रहें । ऐसी परिस्थिति नहीं होनी चाहिए । यह सारी चीजें सोच कर हमें अपना वक्तव्य देना होगा । हम इस रेस्पांसिबिलिटी से और इस प्रकार से यहां पर वक्तव्य नहीं देगें तो मैं समझता हूं कि परदेश नीति की दृष्टि से बहुत ही कठिन परिस्थिति होगी ।

अगर हम राष्ट्रपति महोदय का भाषण पढ़े तो उस में दो चीजें अहम नजर आती हैं । एक तो यह है कि देश के अंदर क्या प्रश्न हैं, उस का उन्होंने उल्लेख किया है और उस के बाद परदेश नीति के बारे में उन्होंने बहुत कुछ उस के अंदर कहा है । यह एक अच्छी और दुरूस्त बात है कि केन्द्रीय सरकार परदेश नीति के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है । यह बहुत अच्छी बात है और यह समझ कर ही उन्होंने इस में ऐसा कहा है, ऐसा मैं समझता हूं और उसी दृष्टि से हमें यहां बोलना होगा ।

बहुत सारी चीजें हैं यहां पर जिन के ऊपर वक्तव्य दिया जा सकता है । बाबू जगजीवन राम ने बहुत ही दुरूस्त कहा है कि यह वक्त जो है यह सोचने का है । उन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, यह कहने का वक्त नहीं है । भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री चरण सिंह ने कहा कि हमने परसीक्यूशन नहीं किया, हम ने कानून की दृष्टि से सब कुछ किया । मैं यह पूछना चाहता हूं, एक लाइयर के नाते हर आदमी जानता है कि किसी आदमी के खिलाफ अगर बहुत सारे केसेज चला दिए गए और फिर उस से कहा जाय कि तुम्हें छूटना है तो कोर्ट के जरिए से छूटो, मगर केस हम तुम्हारे ऊपर चलाएंगे और इस पर यह कहा जाय कि हमने आपका परसीक्यूशन नहीं किया तो क्या वह परसीक्यूशन नहीं होगा ? मेरा कहना यह है कि इस दृष्टिकोण से हमें इस अभिभाषण की ओर नहीं देखना है, हमें इस अभिभाषण की ओर इस दृष्टिकोण से देखना है कि हमारे प्रश्न क्या है और कौन सा मार्ग सही है, कौन सा मार्ग गलत है ? कौन सा मार्ग हमें छोड़ना है कौन सा पकड़ना है, इस दृष्टि से हमें देखना होगा ।

मैं आप का आभारी हूं कि आप ने मुझे बोलने का और अपने विचार रखने का मौका दिया ।

श्री महाबीर प्रसाद (बांसगांव) : माननीय सभापति महोदय, आप ने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्य श्री एस० एम० कृष्ण ने जो प्रस्ताव रखा है तथा जिस का अनुमोदन श्रीमती मोहसीना किदवई जी ने किया है, उस प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया है, उस के लिये मैं आपका आभारी हूं ।

सभापति महोदय, मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को ध्यानपूर्वक पढ़ा और इस माननीय सदन के सदस्यों द्वारा जो अनुमोदन या समर्थन किया गया उस को भी ध्यान से सुना । मैंने इस अभिभाषण को तीन हिस्सों में देखने का प्रयास किया । जब मैं इस परिप्रेक्ष्य में गया तो पहला हिस्सा 24 मार्च, 1977 के पहले का था, उसके पहले जो सरकार थी उस के कार्यक्रम को देखा । उस के बाद मैंने 24 मार्च, 1977 के बाद तथा 14 जनवरी, 1980 के बीच के परिप्रेक्ष्य को देखा, और तीसरे भाग में 14, जनवरी, 1980 के बाद के परिप्रेक्ष्य को देखा । मान्यवर, मैंने यह देखा कोई भी देश हो, भारतवर्ष हो या कोई अन्य देश हो, जब उस की आर्थिक अवस्था, आर्थिक विपन्नता पर हम ध्यान देते हैं, उसके निर्यात और आयात पर ध्यान देते हैं तो 1970-71 में भारत में मुद्रास्फीति की जो स्थिति थी, यदि 100 को आधार मान कर चलें, तो मूल्य सूचकांक 188 था । उस के बाद जब 1977-78 में जाते हैं तो मूल्य सूचकांक 181 पर था, लेकिन जब 1978-79 के बीच आते हैं तो यह मूल्य सूचकांक बढ़ कर 201.3 प्रतिशत हो गया था, अर्थात भारत की अर्थ व्यवस्था में मुद्रास्फीति 20.3 प्रतिशत बढ़ गई थी । इस से साबित हुआ कि तीन वर्षों में या 28-30 महीनों के अन्दर देश की अर्थ-व्यवस्था बहुत ज्यादा बिगड़ी । एसी स्थिति में हमारे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में यह लक्ष्य किया गया है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वह इस अर्थ-व्यवस्था को सुधारने का प्रयास करेगी । मुझे पूरी आशा है कि हमारी सरकार इस मुद्रास्फीति को घटायेगी और उस के आधार पर आयात कम होगा तथा निर्यात बढ़ेगा । किसी भी देश की प्रगति का यह सिद्धांत है कि जब आयात कम होता है और निर्यात बढ़ता है, तो उस देश में समाजवाद आता है अर्थात वह देश आत्मनिर्भर हो जाता है । इसलिये हम को आशा है कि इस वक्त जो भारत की सरकार है, जो नई सरकार बनी है, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जिन सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, उन के आधार पर भविष्य में देश की आर्थिक व्यवस्था को ठीक करने का प्रयास करेगी ।

मैंने अभिभाषण में देखा कि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन-जातियों के आरक्षण के संबंध में उल्लेख था । उसी के आधार पर हम ने यहां 45 वां संविधान संशोधन पास किया । संविधान संशोधन पर चर्चा के समय कुछ माननीय सदस्यों ने कहा कि इस का सारा श्रेय इन्दिरा जी को क्यों दिया जा रहा है, इस का श्रेय तो सब को

दिया जाना चाहिए । मैं आप के माध्यम से उन माननीय सदस्यों से जानना चाहता हूं—उन ढाई-तीन वर्षों में हमारे माननीय बाबू जगजीवन राम जी जैसे वरिष्ठ नेता कहां थे, जब बेलछी का काण्ड हुआ, जब मोरवी का काण्ड हुआ, जब आन्ध्र प्रदेश का काण्ड हुआ, जब कानपुर का काण्ड हुआ ? मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता—हमारे आजमगढ़ जिले में एक गांव है—गूजरपार—वहां हरिजनों के साथ जो अन्याय हुआ उस समय हमारे श्री मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह जी और बाबू जी जैसे नेता कहां थे, वे वहां पर क्यों नहीं गये ? लेकिन श्रीमती इन्दिरा गांधी, जैसा आप सभी जानते हैं, उस समय भी जब बेलछी का काण्ड हुआ, 14 हरिजनों को जिन्दा जला दिया गया वहां पर पानी भरा होने के बावजूद भी हाथी पर चढ़ कर वहां गई उस समय ये लोग कहां थे ?

17.00 hrs.

इसलिए सभापति जी मैं आप के माध्यम से सदन को बता देना चाहता हूं माननीय विरोधी पक्ष के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अहमियत इस बात की है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के हृदय में हरिजनों, गिरजनों, परिजनों अल्पसंख्यकों और दलित लोगों के प्रति प्रेम है । इस लिए जो 45वां संविधान (संशोधन) विधेयक पेश किया गया है, इस का श्रेय श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है । उन की हालत सुधारने के लिए उन में विश्वास है ।

इस के बाद मैं आर्थिक कार्यक्रम की तरफ आता हूं । आर्थिक कार्यक्रम के लिए बीस-सूत्री कार्यक्रम 1974 में लाया गया था लेकिन 24 मार्च 1977 के बाद जब जनता पार्टी की सरकार बनी, उस समय बीस सूत्री कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि पूरे भारत वर्ष में चालू था । उस समय गरीबों, भूमिहीनों, हरिजनों और अनुसूचित और अनसूचित जन-जातियों तथा अन्य पिछड़ी हुई जातियों के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चालू था मगर खेद के साथ कहना पड़ता है कि उस समय, जब जनता पार्टी का जन्म हुआ और उसकी सरकार केन्द्र में बनी तथा दूसरे प्रान्तों में बनी, तो हमारे उस न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को जिस को हम बीस-सूत्री कार्यक्रम कहते हैं, ठप्प कर दिया गया । उस समय मैं एक विधायक था और मैं जानता हूं कि हरिजनों तथा पिछड़ी हुई जातियों के लोगों को कुछ जमीन दी गई थी । दस्तकारों को, हथकरघा वालों को, हरिजनों और अल्पसंख्यक लोगों तथा पिछड़ी हुई जातियों के दूसरे लोगों को बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत कुछ सुविधाएं दी गई थीं, लेकिन जब जनता पार्टी की सरकार बनी, तो उस ने उस सारे काम को ठप्प कर दिया ।

मैं ने राष्ट्रपति जी के भाषण को पढ़ा और उस में यह देखा कि उस में लिखा है कि बीस सूत्री कार्यक्रम में जान डाल कर उसे लागू करने का पुनः प्रयत्न किया जाएगा जब मैंने यह देखा कि बीस सूत्री कार्यक्रम को पुनः लागू किया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि हरिजनों, गिरजनों, परिजनों, अल्पसंख्यकों, दस्तकारों, हथकरघा वालों और अन्य पिछड़ी जातियों, तथा अन्य वर्गों के लिए आर्थिक कार्यक्रम बनने से उन की आर्थिक उन्नति होगी और वे आगे-बढ़ेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं ।

औद्योगिक क्षेत्र का जहां तक सम्बन्ध है, मान्यवर, मैंने राष्ट्रपति के अभिभाषण को पढ़ा है और इस को मैंने देखा है, । मैंने पहले ही बता दिया है कि मैं तीन पक्षों में इस का अध्ययन करना चाहता हूं । एक तो 24 मार्च, 1977 से पहले हमारी औद्योगिक नीति क्या थी । उस के बाद 24 मार्च, 1977 और 14 जनवरी, 1980 के बीच में औद्योगिक सम्बन्ध क्या थे और उस के बाद औद्योगिक सम्बन्ध क्या होंगे । ये तीन पक्ष हमारे हैं । जब कांग्रेस की सरकार थी, इन्दिरा गांधी जी की सरकार थी, तब हम विशेष कर सरकारी पक्ष अर्थात् सार्वजनिक मंच को मजबूत करते थे लेकिन बीच में हम ने देखा कि इन 28 और 30 महीनों के अर्से में, इस मुद्दत में, प्राइवेट सैक्टर जिस को हम निजी सैक्टर कहते हैं, उस में बढ़ोतरी हुई है । उस समय चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो और चाहे लोक दल की सरकार रही हो, हमें यह शंका हुई कि जब भारतीय संविधान में हम ने समाजवाद, लोकतंत्र और धर्म निरपेक्षता की उद्घोषणा की है, समाजवाद के नाम पर प्राइवेट सैक्टर और निजी व्यवस्था को तूल देने से समाजवाद का जो स्वप्न है, वह दूर हटता चला गया । इसलिए राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में प्राइवेट सैक्टर और सार्वजनिक सैक्टर यानी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक सम्बन्धों की उद्घोषणा की है । राष्ट्रपति के भाषण में इस सम्बन्ध में जो भी कहा गया है, उस की मैं ताईद करता हूं और जानता हूं कि भविष्य में ये सम्बन्ध और अच्छे होंगे जिन के कारण भारत में समाजवाद आ जाएगा ।

महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में मैं ने क्षेत्रीय असन्तुलन के बारे में भी पढ़ा । मान्यवर 24 मार्च, 1977 और 14 जनवरी, 1980 के बीच यह क्षेत्रीय असन्तुलन काफी बढ़ा है जिस के कारण भारत की आर्थिक व्यवस्था खराब हुई है । इस बीच देश के हर भाग—पूर्वी, पश्चिमी, दक्षिणी और उत्तरी क्षेत्रों में क्षेत्रीय असन्तुलन पैदा हुआ है । मैं चाहता हूं कि जो भी उपाय इस क्षेत्रीय असन्तुलन को ठीक करने के लिए बताये गये हैं—जैसे कि वनरोपण, भूमि संरक्षण, उद्योग धंधों की स्थापना—इन उपायों को अपनाकर इस क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर किया जाय । मैं, मान्यवर, यह भी चाहता हूं कि ऐसे स्थानों का सर्वेक्षण किया जाए कि कहां कहां पर इन उपायों को अपनाना है ।

आप के माध्यम से, मान्यवर मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं गोरखपुर जिले की बहुत ही पिछड़ी तहसील बांसगांव से आता हूं । जहां पर आज तक कोई उद्योग धंधा नहीं लगा, जहां पर उद्योग धंधों के लिए रेलवे लाइन की कोई सुविधा नहीं है । वहां पर 1976-77 में रेलवे लाइन का सर्वेक्षण हुआ था । मैं सरकारी पक्ष से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए रेलवे लाइन के काम को आगे बढ़ाया जाए ।

[श्री महबीर प्रसाद]

मान्यवर शिक्षकों और शिक्षार्थियों के विषय में भी मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर जब कांग्रेस की सरकार थी तो उस सरकार के शिक्षा के विषय को संविधान की समवर्ती सूची में रखने का प्रावधान किया था लेकिन जब जनता सरकार आयी तो उसने शिक्षा को समवर्ती सूची से निकाल देने का प्रावधान किया । अतः मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि वह शिक्षा को पुनः समवर्ती सूची में रखने की व्यवस्था करे ।

माध्यमिक शिक्षकों को तथा प्राथमिक शिक्षिकों को समान कार्य के आधार पर समान वेतन मिलना चाहिए । इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये । शिक्षा मंत्री जी शिक्षकों के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करें।

इसी संदर्भ में मैं बताना चाहता हूं कि जनता पार्टी के शासन काल में जो दो सौ करोड़ रूपये का प्रावधान एडल्ट एजूकेशन के नाम पर किया गया था उसका कोई उपयोग नही हुआ । इसलिए में चाहता हूं कि अब माध्यमिक स्कूलों तक शिक्षा को निःशुल्क कर दिया जाए । मान्यवर, यह मेरा सरकार से निवेदन है ।

इस के साथ ही साथ, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकतंत्र भारतीय संविधान में दिया हुआ है । राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भी उसकी घोषणा की गयी है । विरोधी पक्ष के हमारे माननीय चौधरी साहब ने भी लोकतंत्र की बात कही है । मैं जब उत्तरप्रदेश का विधायक था तो उस समय चौधरी साहब वहां विरोधी दल के नेता थे । उस समय भी वे लोकतंत्र की बात करते थे । मान्यवर मैं जाना चाहता हूं कि क्या लोकतंत्र यही है कि एक नागरिक को अपना मत देने का भी अधिकार न हो । क्या यही महात्मा गांधी के सपनों का और भारतीय संविधान का लोकतंत्र है जिसे डा० भीमराव अम्बेदकर ने इस देश को दिया ? मेरे पास मेरठ, बागपत और किराना से लोग आये थे जिन के सिर फूटे हुए थे । बाहें टूटी हुई थीं, पैर टूटे हुए थे । आज तक वे लोग अपने वोट का प्रयोग नहीं कर पाए है । देश को आजाद हुए 30 वर्ष हो गए है । क्या इसको लोकतंत्र कहा जा सकता है और लोकतंत्र के पुजारी अपने आप को लोकतंत्री कहते हैं क्या यह उनको शोभा देता है ? लोकतंत्र के नाम पर, हरिजनों, कमजोर वर्ग के लोगों और अल्पसंख्यकों को जो आज के इस वैज्ञानिक युग में जब दुनिया कहीं से कहीं चली गई है, आगे बढ़ चुकी है, ऐसी हालत में उनको वोट डालने नहीं दिया जाता है क्या इसके औचित्य को किसी भी आधार पर सिद्ध किया जा सकता है। द्वापर में मैथिली शरण गुप्त ने एक स्थान पर लिखा है :-

पीछे पितर पृष्ठ पोषक हैं
पर भविष्य तो आगे
यदि अपना परिणाम न देखें
तो हम अंध अभागे ।

आपके माध्यम से, सभापति महोदय, मेरा सरकार से यह अंतिम निवेदन है कि जनता पार्टी की सरकार के तीस महीनों के शासन काल में जो देश इतना पीछे हो गया है, उसको हम देखें और भारत को आगे बढ़ाने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में लोकतंत्र, समाजवाद और धर्म निरपेक्षता के सिद्धांतों के आधार पर चलते हूए आगे बढ़ें ।

इन्हीं शब्दों के साथ जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

DR. SUBRAMANIAM SWAMY (Bombay—North East): We sit here today in an entirely new context compared to the 1977 Lok Sabha. It is in one sense a matter of pride for the democratic system in India that the leaders who were thoroughly rejected by the people in 1977 have returned as massively in 1980. But let this be a sobering thought on the ruling party because it is only in a democratic system that this kind of thing is possible. Had there been any other kind of system, once a person goes out of power you never hear of that person again. You perhaps would not even see that person again. It is only in a democracy that people can go out of power and can hope to come back to power. So I think this would be the first sobering thought that all of us should have that this democratic system is worth preserving at all costs. Therefore, let us jointly commit ourselves to strengthening this system and most important of all, to ensure that the definition of democracy as we understand it here is the same as the definition of democracy as they understand it there because even during the emergency the Congress Party conti-

nued to maintain that there was democracy in the country although in the country and outside everywhere it was widely felt that there was no democracy and there was indeed no democracy... (*Interruptions*). Perhaps it was guided democracy. But it was not democracy in the true sense of the word. We have, therefore, to get together and be sure that we understand what democracy is and what we are trying to preserve.

The ruling party has emphasised in all their speeches on the co-operative attitude from the Opposition. Even he Prime Minister said, 'I hope the Opposition does not indulge inobstructive activities.' The President also has elaborately said in his speech towards the end that for a healthy functioning of democracy it should proceed according to well laid down rules and mutual respect should be shown by the Government and the Opposition to each other, harmonising and so on. These are all platitudes. The question is : how are we going to convert it? It is quite clear in our minds that because we lost in the 1980 elections there is no bitterness. We are not bitter that we have lost. I am sure the other side would recognise this. We have not come here with a spirit of bitterness or with a feeling that we have been cheated out of power and we ought to come back in some form or the other.

I would suggest that they must also recognise that this is part of the electoral game. I was very surprised at the number of invectives that were used by so many ruling party Members against Chaudhury Charan Singh. I was particularly surprised because the target seems to be Chaudhury Charan Singh. I consider this as matter of surprise because there is no one on this side who has done more for that party than Chaudhury Charan Singh by the events of July in which he divided the Janata Party and he defected and it was, with their help, that he was able to form the Government which collapsed within a very short time. These people would not be sitting for 2½ years after the mandate had it not been for Chaudhury Charan Singh.

So, I would request you to show some gratitude to Chaudhury Charan Singh when you are giving your speeches. I think there is no bitterness if there has to be a cooperative attitude. Certainly the Opposition is ready to support any good things coming from that side. But, the tone has to be set by the ruling party. What is that tone? In their speeches they said that the Janata Government did nothing; the Janata Party had destroyed the economy and ruined the country etc., etc. It was a little like an election speech. But, we are in Parliament and to-day we have in possession a large amount of data, statistical facts. These are available in our Library. We have one of the finest Libraries in our country. And Parliament Members are expected to make use of it. The statistics show that within the two year's rule of the Janata Party, the rate of growth of national income was 5½ per cent per year whereas in the previous thirty years it was only 3½ per cent per year. It was a much higher rate of growth that was achieved during the Janata rule.

Therefore, this ought to be recognised. If you want to explain it away, then, in your speeches, you must admit this much 'yes, the rate of growth is higher. These are the reasons for it.' To-day, in the morning, in the House during Question Hour, Prof. Madhu Dandavate raised a question of foodgrains Production. In the reply it was admitted that the foodgrains production in the first year was 15 million tonnes which was more than in the previous year, that is in 1975 and 1976, that is, in the emergency year and in the following year. In 1978-79 it was 20 million tonnes more than before. I asked the question to which the Minister obviously did not give the answer. But, what was the foodgrains stock after the abundance of foodgrains production? If he had given the answer, it would have been more than in 1973 and in 1975.

PROF. MADHU DANDAVATE: He exercised his fundamental right of ignorance.

DR. SUBRAMANIAM SWAMY: It would be in fairness that these facts are brought out. In the 2½ years' Janata rule, they were able to bring more villages under the drinking water facility scheme. 46,000 villages were given the facilities of drinking water whereas in the previous thirty years, only in 40,000 villages that they were able to give drinking water facilities. In the Janata Government rule drinking water facilities were available in 46,000 villages. Therefore these statistics are there. And the Janata Government certainly stablised the prices whatever one may say. One has to look at the March, 1977 prices (*Interruptions*). The price of rice particularly at that time was Rs. 6 a kilo. We brought it down to Rs. 2 a kilo. The price of sugar was Rs. 5.50 a kilo and we brought it down to Rs. 2.50 a kilo and, actually, it was even less than this. (*Interruptions*). This is the problem. Prof. Madhu Dandavate says that it was one's exercising the fundamental right of ignorance. The fact is that these are available. In February 1979, we had the misfortune of Mr. Charan Singh's sitting in the Finance Ministry. The price of sugar was Rs. 2.20 per kilo. This was the actual thing. (*Interruptions*). We made the error. That is why we are sitting here. Don't make the errors. Otherwise you will also be here very soon. Therefore, I must say that the prices of almost all the commodities which the poor man uses were brought down during the Janata Party rule. We did make mistakes and that is why we are here. I wish that my party will use the time in the opposition to strengthen the party and be in a position to fight the next General Elections. I am sure that if the ruling party there, instead of solving the people's problems concentrate more on other things, they would also be in the same plight as we are here to-day.

I would request the ruling party, through you, that during their tenure, they do not create any precedent, which can be later on used against you. Every speaker referred to the expulsion of Smt. Indira Gandhi from this House. The anger was on the issue that we used the brute majority to expel a person who was legitimately elected to this House. Where do we get this precedent from! There was a precedent. I was a member of the Rajya Sabha. I was also legitimately elected and once elected the same brute majority was utilised to expel me. The precedent was there available for us. I am sure if that precedent had not been there it would have been very difficult to consider expulsion of Smt. Indira Gandhi. So, I would say to the hon'ble Members opposite not to do anything which you may regret later on and which may be used against you. Today the State Assemblies are being threatened with dissolution. I would certainly say to my colleagues if they did on the pretext that all the MPs of that area have been elected on Congress ticket and they have a precedent they can go for dissolution; yet at the same time I would say that it is for the ruling party to recognise the limitations of its power. The people are not to be taken for granted. Five years later or perhaps even earlier if inner-party problems that you also seem to have get out of proportion then in the next general elections you will have the same problem.

I would like to make one final reference to the Address of the President. I am very sorry to say that two most important problems, namely, problem of slum dwellers in the cities and the problem of land-less labourers have not been touched in the Address. Nothing has been said about it. My friend, Shri Ram Jethmalani, has brought an amendment in regard to slum policy. The Central Government owns lot of land all over the country and on that land over the years slums have come up.

In Bombay there is a proliferation of 'jaunparpatis'. Because they are on Central government land they are not given any amenities of drinking water, etc. If it is a State government land they will get toilet facility, municipal school, drinking water taps, etc. As these 'jaunparpatis' are on Central Government land, the Central Government consistently for the last thirty years refused to allow the State governments and municipalties to give amenities. During our time we were working towards it. We were close to having a policy declared. The first thing I requested the Minister of Works and Housing was to have a discussion on a national slum policy so that we can provide millions of people with basic amenities.

Secondly, Sir, we need radical land reforms in this country. By land reforms I mean where there is meaningful legislation but unfortunately the President's Address does not say anything about it.

Sir, I do welcome para 25 of the President's Address in which he talks about Sino-Indian moves towards normalised relations. I fully support the sentiments expressed. I quote:

> "Sino-Indian moves towards normalised relations, a potentially stabilising factor, were inevitably affected by the Sino-Vietnam conflict. India remains willing to discuss all issues with China including the boundary question in search of a peaceful solution based on equality. We hope to progress also as regards bilateral exchanges."

I fully support the sentiments expressed. We do need new initiatives towards China and it would be a stabilising factor.

Sir, I would like to conclude my thoughts here with a final plea that we are today starting something anew. In fact, Opposition and the Ruling party should call it quits and work out a new relationship so that we can function within the democratic system—as the world understands it—and safeguard the human rights within the country.

श्री विरधी चन्द जैन (बाडमेर) : सभापति महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। सबसे पहले मैं भारत की जनता का अभिनन्दन करता हूं, जिन्होंने केन्द्र में स्थिर शासन दिया, कांग्रेस (आई) को बहुमत में शासन दिया और केन्द्र में श्रीमती इंदिरा गांधी को नेतृत्व प्रदान किया। देश में आज जो स्थिति है, वह बहुत ही नाजुक है। देश बहुत ही नाजुक स्थिति से गुजर रहा है हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है। कानून और व्यवस्था की स्थिति प्रान्तों में बहुत ही दयनीय है और मंहगाई चरम सीमा तक पहुंच गई है। इन समस्याओं को हल करने के लिये केन्द्र को और जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनको सब को मिलकर काम करना होगा। केन्द्र कितना भी प्रयास करे, जब तक प्रान्तों की सरकारों का सहयोग नहीं होगा, तब तक मंहगाई पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता, तब तक कानून और व्यवस्था पर नियन्त्रण नहीं किया जा सकता। इसलिये यह आवश्यक है कि केन्द्र और प्रान्तों की सरकारों का सहयोग हो।

जनता ने जो निर्णय दिया है उस निर्णय ने यह साबित कर दिया है कि हिन्दुस्तान की जनता कांग्रेस (आई) का शासन चाहती है, केन्द्र में भी चाहती है और प्रान्तों में भी चाहती है। परन्तु प्रश्न यह है कि जनता को अवसर मिले, तभी वह प्रान्तों में शासन दे सकती है और यह भी एक जटिल समस्या है कि किस प्रकार प्रान्तों को...

एक माननीय सदस्य : केरल में दिया है।

श्री विरधी चन्द जैन : केरल की स्थिति अलग है, परन्तु दूसरे प्रान्तों में और तरह की स्थिति है। इसलिये और दूसरे प्रान्तों के बारे में अलग अलग ढंग से सोचना पड़ेगा। हिन्दुस्तान की जनता ने हमारे पार्लियामेन्ट के मेम्बर्स के पक्ष में मत नहीं दिया है बल्कि कांग्रेस (आई) पार्टी के पक्ष में मत दिया है। मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार को इस के लिये मजबूत कदम उठाने चाहिये कि जहां कुशासन चल रहा है, वहां उस को कैसे दूर किया जाय। मैं अपने राजस्थान प्रान्त की बात कह रहा हूं। वहां भयंकर अकाल की स्थिति है। 33 हजार गांवों से 26 हजार गांव अकाल से पीड़ित हैं। वहां "फूड फार वर्क" के नाम से कुछ काम चल रहा है, जो ग्राम पंचायतों द्वारा चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायतें और उन के सरपंच इतने योग्य नहीं हैं और जहां कोई सरपंच है भी, वे भी 100 से अधिक मजदूरों को काम नहीं

[श्री विरधी चन्द्र जैन]

पाते, क्योंकि उन के पास स्टाफ नहीं है, केवल एक ग्राम क्लर्क (ग्राम सेवक) उन के पास होता है, जो इस का काम करता है । वह इतना काम कर नहीं सकता और अकाल की समस्या बहुत ही भयंकर है । हमारे राजस्थान प्रान्त में ढाई करोड़ की जनसंख्या में से पौने दो करोड़ की जनसंख्या अकाल से प्रभावित है और सिर्फ दो लाख मजदूर कार्य में लगे हुए हैं । मजदूरों को मजदूरी न मिलने से कुछ लोग हरियाणा की तरफ, कुछ पंजाब की तरफ और कुछ गुजरात की तरफ चले गये हैं । राजस्थान की सरकार उनको मजदूरी नहीं दे पा रही है । केन्द्रीय सरकार को इस गम्भीर प्रश्न को देखना चाहिए । आगे के प्रश्न और भी गम्भीर होंगे, क्योंकि अकाल की स्थिति गर्मी के दिनों में और भी तीव्र होगी । हमारे क्षेत्र बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में सिर्फ खरीफ की फसल होती है और वह फसल भी बिल्कुल नष्ट हो चुकी है । उन क्षेत्रों में यदि केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार की मदद नहीं करेगी तो इस समस्या का समाधान नहीं हो सकेगा, क्योंकि राजस्थान सरकार की खुद की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वह इस भयंकर अकाल का सामना कर सके । 1967-68 में भी भयंकर अकाल पड़ा था उस समय केन्द्रीय सरकार ने 150 करोड़ रुपये की मदद दी थी इसी तरह की मदद इस समय भी देने से वहां के लोगों को भुखमरी से बचाया जा सकता है । इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार राजस्थान सरकार के मुख्य मंत्री जी और वहां के गवर्नर को बुला कर वहां की स्थिति की पूरी तरह से जांच करे और स्थिति को समझ कर पूरी तरह से मदद करे ।

पानी की समस्या की यह हालत है कि बहुत से गांवों में पानी बिलकुल नहीं है और यदि कहीं है भी, तो खारा पानी है । उन गांवों में पानी ट्रक्स और टैम्पोज़ के द्वारा पहुंचाया जाता है परन्तु कितना पानी मिलता है ? एक व्यक्ति को केवल आधा गैलन मिलता है । जबकि शहरों में एक व्यक्ति पर 20-25 गैलन पानी खर्च किया जाता है, उन गांवों में पीने के लिये आधा गैलन या एक गैलन से अधिक पानी नहीं मिल रहा है । जब मनुष्यों की यह हालत है तो पशुओं की हालत का अन्दाज़ा आप स्वयं लगा सकते हैं । पशुओं की भी वहां बहुत बुरी हालत है । इस प्रकार की स्थिति को देखते हुए मैं आप से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप राजस्थान के अकाल के प्रश्न को गम्भीरता से लें और राजस्थान सरकार की अधिक से अधिक मदद करें ।

दूसरी बात, मैं विशेष रूप से यह कहना चाहता हूं कि प्रौढ़ शिक्षा के नाम पर राजस्थान में आर०एस०एस० का प्रचार हो रहा है, वे हर प्रकार से एटमासफिअर को प्रयजन करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां की जनता के दिमाग़ों को विकृत कर रहे हैं जो हमारे देश के लिये बहुत हानिकारक है । प्रौढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में मैं यह निवदन करना चाहता हूं---मेरा 30 वर्षों का अनुभव है---प्रौढ़ शिक्षा पर अब तक जो राशि व्यय की गई उसका कोई विशेष लाभ नहीं हुआ । हमारे कांग्रेस के राज्य में भी और जनता पार्टी के राज्य में भी जो पैसा खर्च हुआ उसका सही उपयोग नहीं हुआ । प्रौढ़ लोगों की पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है । व लोग लगातार दिन भर काम करते हैं, रात को उन्हें पढ़ाने की कोशिश की जाती है । यह ठीक है कि कोई बहुत डेडिकेटेड टीचर हों या वर्कर हों, वे उनको कुछ थोड़ा बहुत पढ़ा लें, लकिन वैसे यह कार्यक्रम बिल्कुल असफल रहा है । मेरा सुझाव है कि प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम पर जो 200 करोड़ रुपये की राशी खर्च की जा रही है उसका डायवर्शन करके उस धनराशि को प्राइमरी एजूकेशन पर खच किया जाना चाहिये और उस पर ही सब से ज्यादा ज़ोर दिया जाना चाहिये । प्राइमरी एजूकेशन पर ज्यादा ज़ोर देंगे, तो मैं समझता हूं कि हमारी समस्या हल हो सकेगी ।

ड्रिकिंग वाटर के सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहता हूं । केन्द्रीय सरकार ने जो पालिसी एडाप्ट की है, उस के अनुसार जो "प्राबलेमेटिक विलेजेज़" है समस्याप्रद गांव है उन के लिये 60 करोड़ रुपया केन्द्रीय सरकार प्रान्तों को दे रही है । दूसरे राज्यों के मुकाबले हमारे राज्य में गांवों की स्थिति कुछ भिन्न है । उत्तर प्रदेश और बिहार में 15 गांवों को पाईप लाइन द्वारा जोडने पर जो खर्चा आता है हमारे यहां उतना खर्चा एक गांव पर आता है । हमारे कृषि मंत्री जी ने अभी हाल में स्टेटमेन्ट दिया था कि हम 5 वर्षों में पीने के पानी की समस्या को हल कर देंगे । आप पानी की समस्या को हल करने के लिए पांच वर्ष की बात कह रहे है । पांच वर्ष में अगर आप इस समस्या को हल कर देते हैं, तो यह एक बहुत बड़ी बात होगी । हम 30 वर्षों में पानी की समस्या हल नहीं कर पाए । हमारे राज्य में 33 हजार गांवों में से 24 हजार गांवों में पानी की समस्या है और वहां पर हम लोगों को शुद्ध पानी नहीं दे सके हैं । बहुत सी जगहों पर तो पानी है ही नहीं और उन गांवों में हमें पानी पहुंचाना है । इसलिए पानी की समस्या को प्राथमिकता देनी है और इस में यह देखना है कि उन सभी गांवों को हमें मिलाना है जहां पर पानी नहीं है । हमारे गांव 50 वर्ग मील और 100 वर्ग मील में बाड़मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में फैले हुए हैं और उन गांवों को मिलाने के लिए बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ेगा और पैसा खर्च करना पड़ेगा । इसलिए मेरा यह कहना है कि इसके लिए हमें पापूलेशन बेसिस को अख्तियार नहीं करना चाहिए बल्कि क्षेत्रफल को इस काम को करने

के लिए देखना पड़ेगा । आज हम देखते हैं कि क्षेत्र बड़े विस्तृत हैं और उन में अगर आप सब गांवों को पानी देंगे, तो आप को बहुत अधिक खर्च करना पड़ेगा । इसलिए इस समस्या के बारे में केन्द्र सरकार जो पापूलेशन बेसिस की नीति अपना रही है, उससे राजस्थान को कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि राजस्थान का जो क्षेत्र है, वह बड़ा विस्तृत है और क्षेत्रफल का बेसिस आप को बनाना चाहिए और पापूलेशन का बेसिस नहीं होना चाहिए । इस दृष्टि-कोण से इस समस्या के बारे में व्यवस्था की जानी चाहिए ।

अब मैं कुछ मुद्दे और हैं, जिन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं । हम 30 साल से प्रयास कर रहे हैं लेकिन हम ग़रीबों को कानूनी सहायता नहीं दे सके । स्थिति यह है कि अभी तक वे अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं सकते । खेतों के बारे में अगर बेदखली हो जाए, खेतों से उन ग़रीबों को निकाल दिया गया और जनता पार्टी के राज्य में निकाला गया है, तो वे कुछ नहीं कर सकते हैं । हमारी कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अन्दर भूमि-सुधार के नाम पर अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जो जमीन एलोट की थी, तो उन को जहां से निकाल दिया गया, वहां के जमींदारों ने, जागीरदारों ने और राजाओं ने उन को एलोट की गई जमीनों से निकाल दिया । उन को जमीन रेस्टोर करने के लिए हमें उन को कानूनी सहायता देनी चाहिए ।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कानूनी सहायता के लिए, मैंने यह देखा है, जो वकील मुकर्रर किये जाते हैं, वे सब से इनफीरियर वकील, सब से अयोग्य वकील होते है और उन्हीं की नियुक्ति की जाती है । इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर हम कानूनी सहायता देना चाहते हैं, लीगल एड देना चाहते हैं, तो अच्छे से अच्छे वकील मुकर्रर किये जाएं, जो दूसरे वकीलों का अच्छी तरह से मुकाबला कर सकें । ऐसी हमें व्यवस्था करनी चाहिए और अगर आप यह नहीं कर सकते, तो एक बात मैं सुझाव के तौर पर यह कहना चाहता हूं कि जो सीनियर एडवोकेट हैं, उनके लिए यह कम्पलसरी कर दिया जाएं, कि उन को ऐसे ग़रीब लोगों के लिए दो, तीन केस लड़ने पड़ेंगे । इस तरह की एक कन्डिशन, एक प्रीसीडेंट बना दिया जाए, ताकि उन को उन के केस लड़ने पड़ें । अभी जो लीगल एड दी जाती है उन ग़रीब लोगों को, तो उस में ऐसे वकीलों को रख दिया जाता है, जो केस फाइट नहीं कर सकते और इस का नतीजा यह होता है कि उन की डिफ़ीट होती है और फिर उनमें अनइजीनेस पैदा हो जाती है । तो लीगल एड के बारे में मैं यही कहना चाहता हूं कि पूरी दिलचस्पी लेकर केन्द्रीय सरकार को एक योजना बनानी चाहिए और प्रान्तीय सरकारों को इस सम्बन्ध में सचेत करना चाहिए ताकि ग़रीब आदमी अपने अधिकारों के लिए लड़ सकें । इस प्रकार की स्थिति बनाने की जरूरत है ।

एक बात मैं विशेष तौर पर बोंडेड लेबर के बारे में कहना चाहता हूं । यह हमारे देश के लिए एक बहुत ही बुरी चीज है और हमारे राजस्थान में बोंडेड लेबर अभी तक चल रही है । एक दफ़ा उन को कर्ज दे दिया, तो पांच साल के लिए, दस साल के लिए और यहां तक कि जिन्दगी भर के लिए बोंडेड लेबर के रूप में उन को काम करना पड़ता है । कानून इस सम्बन्ध में बनाए गये है । केन्द्रीय सरकार ने बनाए हैं और राज्य सरकारों ने भी बनाए हैं परन्तु उन का इम्प्लीमें-टेशन नहीं होता है, उन का कार्पान्वियन नहीं होता है, क्योंकि बोंडेड लेबर रखने वाले ऐसे आदमी हैं जो प्रभावशाली होते है । वे पार्टी का प्रोटेक्शन पा लेते हैं और उस प्रोटेक्शन की वजह से उन पर कोई कार्यवाही नहीं होती है । इसलिए मेरा कहना यह है कि जो व्यक्ति बोंडेड लेबर रखता है, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाने चाहिए और यह कार्यक्रम सभी पार्टियों को मिल कर करना चाहिए । यह किसी एक पार्टी का प्रश्न नहीं है, यह सभी पार्टियों का प्रश्न है और मेरा निवेदन यह है कि इस बोंडेड लेबर के प्रश्न को गंभीरता से लेना चाहिए ।

मैंने कुछ समस्याएं आप के सामने रखी हैं और वे महत्वपूर्ण समस्याएं हैं और इन को हल किया जाना चाहिए । अगर इन समस्याओं को हमें हल करना है तो हमें कुछ रद्दो-बदल करनी पड़ेगी । हमें अपने आर्थिक, सामाजिक ढांचे में आमूल-चूल परिवर्तन करना पड़ेगा । हमें ऐसे ठोस कदम उठाने पड़ेंगे जिनसे कि गरीबी मिटे । हमें इसके लिए विशेष योजनाएं बनानी पड़ेंगी । इसके लिए न केवल सरकार को ही बल्कि इस सदन के प्रत्येक सदस्य को और प्रत्येक जन-प्रतिनिधि को भी प्रयास करना पड़ेगा । यह प्रयास करके ही हम अपने देश का कल्याण कर सकते है ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : आदरणीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आये धन्यवाद के प्रस्ताव पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर प्रदान किया ।

श्रीमन्, आप जानते हैं और यह सदन जानता है कि राष्ट्रपति जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का परिचायक होता है । इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि यह राष्ट्रपति का अपना भाषण नहीं होता, बल्कि यह सेक्रेटेरियेट में लिखा जाता है । क्योंकि उन नीतियों का संचालन करने की जिम्मेदारी सरकार की हुआ करती है । सरकार जो काम करना चाहती है, जिन नीतियों पर चलना चाहती है उनका ब्यौरा वह अभि-भाषण में देती है । यह एक ऐसा दस्तावेज है जिसको पूरा करने के लिए सरकार हमेशा प्रतिबद्ध रहती है और उसको रहना भी चाहिए ।

श्रीमन्, मैंने इसको आद्योपान्त पढ़ा है । इस छोटे से अभिभाषण में 33 पैराग्राफ हैं । लेकिन

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

ऐसा लगता है कि जैसे गागर में सागर भर दिया गया हो। इसमें कोई ऐसा कोण नहीं है कि जिसमें भारत में जो समस्याएं हैं, उनका निदान न हो। अभी विरोधी दल के माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी की बात कही। आपने सेल्स टेक्स खत्म करने की बात कही थी लेकिन आप उसे खत्म नहीं कर पाये। हमने जो इसमें लिखा है उसमें बेरोजगारी को दूर करना भी आ जाता है। जब आर्थिक समस्याओं का निदान होगा, खेतीबाड़ी ठीक होगी और उत्पादन बढ़ेगा तो बेरोजगारी भी अपने आप दूर होगी। बेरोजगारी तो आप स्वयं जानते हैं कि इतनी बड़ी समस्या है कि इसको एकदम दूर नही किया जा सकता है। न इसे पिछली सरकार की तरह झूठे वायदे कर के टाला जा सकता है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो समस्याएं पैदा हो गई हैं, किसानों की अगर समस्याएं हैं तो वह किसान के बेटे ने पैदा की हैं। जिसको किसान का बेटा कहा जाता है, उसके राज में डीजल, मिट्टी का तेल, बिजली सभी गायब। इनकी बात तो हम यों भी कह सकते हैं कि शायद इन चीजों का सम्बन्ध बाहर की सप्लाई से ताल्लुक रखता था। पर चीनी कहां चली गई? आपके राज में चीनी कहीं देखने को नहीं मिल रही है।

मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूं। 65 प्रतिशत चीनी जो लेवी की थी, वह चीनी कारखाने वालों ने राशन की दुकानों को देना बन्द कर दिया। नतीजा यह है कि शक्कर ब्लेक मार्किट में पांच छः रुपये किलो बिक रही हैं। एक गरीब आदमी को राशन की दुकान से छंटाक भर चीनी नहीं मिलती है। (व्यवधान) आप यह भी नहीं कह सकते कि वहां लोकदल की सरकार है या जनता पार्टी की सरकार है। हम दोनों की ही सरकार मान लें तो दोष आप दोनों का ही है। बुद्धि एक ऐसा विषय है कि न तो इसको मैं विरोधी दल के भाइयों को कहीं से उधार ला कर दे सकता हूं और न किसी दुकान से इसकी कोई पुड़िया मिलती है जो मैं आठ आने या एक रुपये में वहां से ला कर इनको खिला दूं। बजाय बीच में टोका टाकी करने के हमारे विरोधी दल के भाई अगर अपनी बुद्धि को स्वयं ही तीव्र करें तो ज्यादा अच्छा होगा।

सभापति महोदय, ये सभी समस्याओं के जन्मदाता ढाई तीन साल के शासन में हो गए हैं। जब श्रीमती इंदिरा गांधी का शासन काल समाप्त हुआ उसके पहले उनकी एमरजेंसी का जो समय था जिसको आप बुरा कहते है मैं समझता हूं कि वह एक ऐसा समय था जब उत्पादन सब से ज्यादा बढ़ा था, बेरोजगारी सबसे ज्यादा दूर की गई है, महगाई अधिकतम कम की गई है, कोई ऐसा काम नहीं था कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जो जनता की भलाई के लिए हो और उस पर काम न किया गया हो।

आप और हम दो ों को जनता को धन्यवाद देना चाहिए। 1977 में जनता न आपको बिठाया और तीन साल के बाद 1980 में जिन को यही से उतारा था उन्हें शासन में दुबारा ला कर बिठा दिया।

17.46 hrs.

[MR. SPEAKER *in the Chair*]

जनता बेवकूफ नहीं है मूर्ख नहीं है। वह अपने अधिकारों को समझती है। कौन उसे फायदा देता है, किससे उसे लाभ हो सकता है, कौन इस देश में सरकार को चला सकता है, कौन इस देश को स्थिर सरकार दे सकता है कौन इस देश का भविष्य उज्जवल कर सकता है, कौन इस देश में बातें बनाने के बजाय काम ज्यादा कर सकता है, इस बात को वह अच्छे तरीके से जान गई है। इसलिए पौने तीन साल में उसने उस सरकार को जिसको उसने बहुत प्रचन्ड बहुमत से चुना था, हटा दिया। मुझे यह कहने में भी कोई हिचक नहीं है कि यह सरकार भी अगर अच्छा काम नहीं करेगी तो जनता इतनी जागरूक है कि आपको कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी और जनता इसे भी अपने आप उतार कर फेंक देगी। यह समय ही बताएगा कि किसने कितना अच्छा काम किया है। जो जज है वह जानता है। वह देख रही हैं आपने क्या किया। आपने सिवाय इस ढाई तीन साल के अन्दर श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री संजय गांधी को जेल में डालने की योजनाएं बनाने के सिवाय क्या किया यह आप हमें बताएं।

एक माननीय सदस्य: आप तो मांफी मांग कर आ गए थे।

श्री हरीश कुमार गंगवार: अगर हिन्दुस्तान भर में कहीं किसी भी जगह से कोई दस्तावेज लाकर आप मुझे यह दिखा दें कि मैंने माफी मांगी थी तो मैं यहां से इस्तीफा दे दूंगा (व्यवधान) इस में कोई शक नही है कि मैं जन-संघ का एम एल ए था। लेकिन जन संघ वालों ने जब अपना सब घोषणा पत्र समाप्त कर दिया तो मैं क्या कर सकता था। श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी बैठे हुए हैं। वह जानते हैं कि जब हम मैम्बर बनाने जाया करते थे तो उस में लिखा होता था कि अखंड भारत होगा, किसानों का लगान आधा होगा, गोवध बन्द होगा, हिन्दी हिन्दुस्तान की राष्ट्र भाषा होगी, अणु बम बनेगा आदि। जब आप जनता पार्टी में मिले तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा आपका सिद्धान्त इस जनता पार्टी के बसूलों में शामिल किया गया? कोई भी जन संघ वाला उठ कर बता दे। जन संघ वालों ने पूरे का पूरा अपना दल बदल किया है और जनता पार्टी के सामने अपने घुटने टेके हैं। एक भी सिद्धान्त उस में शामिल नहीं है जो जनता पार्टी का चुनाव घो ा पत्र है उस में। मैंने यह मुनासिब समझा कि पांच लंगड़े मिल जाएं तो एक साबुत आदमी नहीं बन जाता है उसी तरह से ऐसे लोग जिन की नीतियां खाली कुर्सी के लिए बनी हैं समाजवाद को खाली

को खाली जो धोखा देना चाहते हैं, उनके साथ न रह कर असली समाजवाद जिस के साथ है, उसके साथ जाया जाना चाहिये, उनके साथ समझौता किया जाना चाहिये। ऐसा करके मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया है

मैं आप से यह पूछना चाहता हूं कि या यह सच नहीं है कि आपने चोर बाजारी को रोकने के लिए कानून बनाया, आर्डिनेन्स जारी करवाया? हिन्दुस्तान भर में यह बता दीजिये कि कितने आपने चोर बाजारियों को पकड़ा? एक भी नहीं। हां इस काम में जरूर उस अध्यादेश का उपयोग किया कि उससे रुपया वसूल कर लें और चुनाव लड़ें। पर एक भी आदमी ब्लैक मार्केट के आरोप में उस तरह से नहीं पकड़ा गया जिस तरह से पकड़ा जाना चाहिये था। और ब्लैक मार्केटिंग बराबर होती रही।

हरिजनों पर अत्याचार किये गये, हरिजनों के आम मसीहा बन कर बैठे थे लेकिन जगह जगह पर उन पर जो अत्याचार हुए उनके बारे में अन्य सदस्यों ने कहा है, मैं फिर उनका जिक्र नहीं करना चाहता। आप क्या करना चाहते थे वह आप सुन लीजिये। राजनारायण जी, कार्यकारी अध्यक्ष लोकदल ने स्पीच दी, उस समय जनता "एस" थी, लोकदल बाद में बना, उन्होंने कहा कि फ़रवरी के बाद चुनाव होने चाहियें। 15 दिन तक अखबारों में खबर आती रही कि लोगों की मांग आई है कि चुनाव के लिए अभी समय ठीक नहीं है, सूखा है और फ़रवरी के बाद चुनाव होना चाहिए। इसमें आपकी मंशा क्या थी? आप चाहते थे कि हरिजनों का आरक्षण समाप्त हो जाय। इसलिए चुनाव नहीं कराना चाहते थे। और हमने देखिए कि सीट पर आते ही सब से पहला काम यही किया और हरिजनों के हितों की रक्षा की। इसी से जाहिर होता है कि आप क्या चाहते थे, और हम क्या कर रहे हैं। पूत के पांव पालने में मालूम हो जाते हैं। हमने अच्छे कामों से शुरूवात की है, और आपको विश्वास दिलाते हैं कि अगर आप इसी तरह से थोड़ा हमको जोश दिलायें, बीच बीच में कुछ चुटकियां लेते रहें तो हमारा जोश और भी बढ़ेगा और हम और अच्छे काम करने में लगेंगे।

एक बात की ओर और मैं सदन का तथा राष्ट्र का ध्यान दिलाना चाहता हू कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चौधरी चरण सिंह के रहते निष्पक्ष नहीं हो सकते। मैं उम्मीद करुगा और आवाज उठाता हूं कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कोई व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों के और बीच के जिलों के कम से कम 50 क्षेत्र ऐसे होंगे जहां की पोलिंग बूथों का घेराव किया गया।

एक माननीय सदस्य : पाकिस्तान के बुलायेंगे चुनाव कराने को?

श्री हरीश कुमार गंगवार: दूसरों को वोट डालने नहीं दिये गये और एक ही आदमी मोहर लगा कर सारे बलट पेपर डाल गया। और इसी लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो लोक दल की जीत हुई है अगर समीक्षा करें तो आधे से ज्यादा सीटें ऐसी निकलेंगी जहां पोलिंग बूथ का घेराव कर के जबरदस्ती वोट डलवा लिये गये। मैं चुनाव जीता, जीतने के बाद लोक दल के लोगों ने मेरे चुनाव कार्यालय पर पिस्तौलों और बन्दूकों से हमला किया। दूसरे आपके यहां श्री राम चन्द्र विकल को बुरी तरह से घायल किया गया। यह इस बात का सूचक है कि आप शांतिपूर्ण चुनाव में विश्वास नहीं रखते हैं, निष्पक्ष चुनाव में विश्वास नहीं रखते हैं। धांधलेबाज़ी और तानाशाही करना चाहते हैं। तानाशाह आप श्रीमती इन्दिरा जी को बताते हैं। यह तानाशाह कौन है? आप यहां हाउस में कभी बैठे नहीं और प्रधान मंत्री देश के बने रहे। आपको राष्ट्रपति ने बुला लिया, उनको हक है मैजारिटी हो माइनारिटी हो, किसी भी आदमी को बुला सकते हैं। आज भी संविधान हमारा इसमें मौन है कि किसको बुलायें। जिसे चाहें राष्ट्रपति बुला सकते हैं प्रधान मंत्री पद देने के लिए। आपको प्रधान मंत्री बना दिया। आपका यह काम था कि आप अपना बहुमत सिद्ध करते क्योंकि उन्होंने विश्वास का मत प्राप्त करने को आपको समय दिया। जिस दिन विश्वास का मत प्राप्त करना था, उस दिन सीधे जा कर इस्तीफ़ा दे आये, लोक सभा को भंग करा दिया और चुनाव की घोषणा कर दी गई। उसके बाद चार चार, पांच पांच, मिनिस्टरों ने इस्तीफ़े दे दिये, पार्टी की पार्टी सरकार छोड़ कर चली गई, चौधरी चरण सिंह अल्पमत में हो गये, लेकिन उनकी कुर्सी उनको छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं कैसे कहूं कि वह प्रधान मंत्री का पद को नहीं छोड़ पा रहे थे।

यह अच्छा नहीं होगा। प्रधान मंत्री की कुर्सी उनको छोड़ नहीं पा रही थी। वह कुर्सी ऐसे चिपक गई कि जब जनता ने वोट के द्वारा बाहर निकाल दिया, तब मजबूर हो कर वह बाहर गये। वह तो चुनाव कराना नहीं चाहते थे। उनकी मंशा देख कर राष्ट्रपति को स्वयं घोषणा करनी पड़ी कि देश में चुनाव कराये जायेंगे। चौधरी साहब ने घोषणा नहीं की।

वह कहते हैं कि इन्दिरा गांधी निरंकुश शासक थी। अगर वह 1977 में चाहती, तो एक साल और हुकूमत करती---संविधान के अनुसार, क्योंकि एक साल अभी बाकी था। लेकिन वह प्रजातंत्र में विश्वास रखती थी, इसलिए उन्होंने चुनाव की घोषणा कर दी। अगर एक साल और चुनाव न कराये होते, तो बहुत से विरोधी दल के लोग, जो जेल में पड़े हुए थे, माफ़ी मांग मांग कर कांग्रेस में शामिल हो कर इधर ही आ गये होते। हमारे मित्र इंदिरा गांधी को प्रजातंत्र विरोधी और निरंकुश बताते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि वे कौन सी राजनीति पढ़ते हैं। वे अपनी राजनीति को फिर से सुधारें। वे अच्छी किस्म की किताबें पढ़ा करें। इधर-उधर की किताबों से काम नहीं बनेगा।

[श्री हरीश कुमार गंगवार]

मेरे साथी, श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा है कि राष्ट्रपति अपने अभिभाषण में नियोजन का जिक्र करना भूल गये। मेरा खयाल है कि चौधरी चरण सिंह और श्री राजनारायण भूल गये। वे लोग परिवार नियोजन के कारण कांग्रेस सरकार को हटा पाये थे। इसलिए जहां जहां नियोजन शब्द लगा था, चौधरी चरण सिंह और श्री राज नारायण उसको भूल गये कि कहीं हमारी सरकार भी इस नियोजन से न चली जाये। योजना बनाने की बात तो दूर, उन्होंने नियोजन शब्द ही नहीं रखा।

मैं जहां से चुन कर आता हूं, वहां बीस हजार बंगाली शरणार्थी बसे हुए हैं। वे शहर से कम से कम चालीस मील दूर, शारदा नदी के पार और दस पंद्रह मील दूर बसे हुए हैं। उनकी फूस की झोपड़ियां हैं, बांस के टट्टर बंधे हुए हैं। न उनके पक्के मकान हैं, न पाठशाला या स्कूल हैं, न डाकखाने खुले हुए हैं और न कोई सड़कें ही हैं। केन्द्र से जो सहायता मिलती थी, जनता पार्टी की सरकार ने ढाई साल से उसको बन्द कर रखा है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वह इन शरणार्थियों की, जिनमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग भी हैं, समस्याओं का हल तुरन्त करें। उन को ग्राण्ट दें और जो पुवांया में रेलवे लाइन अंग्रेजों के जमाने में पड़ी हुई थी, वह बाद में उठा ली गई थी, उस से जनता को बड़ी परेशानी है। यह क्षेत्र शाहजहांपुर जिले में पड़ता है उस का सर्वे हो चुका है। उस रेलवे लाइन को फिर से डाला जाना चाहिए।

अन्त में, मैं एक शेर पढ़ देना चाहता हूं --

जो हो तारीफ़ कम है इन्दिरा तेरी सियासत की,
यह देसाई की अर्थी जा चुकी है या कि तिजारत की।

मैं आप का और माननीय विरोधी दल के सदस्यों का भी बहुत आभारी हूं कि मुझे बोलने का भरपूर मौका दिया। धन्यवाद।

18.00 hrs.

ANNOUNCEMENT *RE*: CANCELLATION OF LUNCH BREAK

MR. SPEAKER: A suggestion was made today that in order to make more time available for the discussion on the Motion of Thanks, lunch recess might be dispensed with tomorrow, 29 January, 1980. If the House agrees, we may agree to the suggestion.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. SPEAKER: Accordingly, there will be no lunch recess tomorrow.

I would also like to state that Members may please conclude their speeches on the Motion of Thanks on 29 January and the Prime Minister would reply to the Debate on the Motion on 30 January, 1980.

If the House so desires, we may continue for half-an-hour more now.

SEVERAL HON. MEMBERS: No.

MR. SPEAKER: All right.

18.02 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Tuesday, January 29, 1980/Magha 9, 1901 (Saka).

GMGIPND—SI—2364 LS—21-2-80—890.